राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सांसद जया बच्चन के बीच बहस हो गई। जया बच्चन ने धनखड़ की 'टोन' पर आपत्ति जताई थी,जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने इस आपत्ति पर कड़ा एतराज जताया।

जनहितैषी

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्षः29 अंकः240 दिनांकः10-08-2024 शनिवार मूल्यः1 रूपया 50 पैसा पृष्ठः4 अहमदाबाद M

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की जमानत के वक्त 'जमानत नियम है और जेल अपवाद' सिद्धांत का हवाला दिया। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद थे।

राज्यसभा में जोरदार हंगामा, उपराष्ट्रपति और जया बच्चन के बीच हुई बहस, सपा सांसद ने कहा

आपकी टोन स्वीकार्य नहीं

नई दिल्ली(ईएमएस)। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सांसद जया बच्चन के बीच बहस हो गई। जया बच्चन ने धनखड़ की 'टोन' पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने इस आपत्ति पर कड़ा एतराज जताया।

दरअसल, जया बच्चन ने कहा कि मैं एक कलाकार हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज और भावों को समझती हूं। मुझे माफ करें, लेकिन आपका टोन स्वीकार्य नहीं है। हम सहकर्मी हैं।

धनखड़ ने कही ये बात

जया बच्चन के इतना बोलते ही उपराष्ट्रपति ने जया बच्चन को बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपने बहुत नाम कमाया है। एक अभिनेता निर्देशक का विषय होता है। आप वह नहीं देख पा रहे हैं जो मैं यहां से देख रहा हूं। आप भले ही एक सेलिब्रिटी हों, लेकिन आपको शिष्टाचार समझना होगा।

जया बच्चन और सभापति के बीच हुई इस बहस के बाद विपक्षी सांसदों से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण को अनुचित बताया और निंदा प्रस्ताव पेश किया।

वॉकआउट के बाद जया बच्चन ने मीडिया से कहा कि कि मैंने सभापति के टोन पर आपत्ति जताई। हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं। हम सब वरिष्ठ हैं, खासकर जब नेता विपक्ष (मल्लिकार्जुन खरगे) बोलने के लिए खड़े हुए उन्होंने माइक बंद कर दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये परंपरा के खिलाफ है। अगर आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो हम क्या करने आए हैं? वो हमेशा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रेटी होंगी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये महिलाओं का अपमान है। मुझे माफी चाहिए।

विपक्ष द्वारा वॉकआउट करने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह न केवल सभापति का अपमान है, यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतंत्र और संविधान का भी अपमान है। गैर-जिम्मेदार विपक्ष देश को अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है।

मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आए

-दिल्ली शराब नीति केस में बेल

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट नेउन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में जमानत दी। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि संविधान की वजह से जमानत मिली। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे।

सिसोदिया तिहाड़ से सीधे अरविंद केजरीवाल के घर गए। उनकी पत्नी सुनिता केजरीवाल और परिवार के लोगों से मिले। शनिवार को वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जा सकते हैं। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च, 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

-चाय पार्टी में पीएम मोदी और राहुल गांधी एक-दूसरे का अभिवादन करते नजर आए

नई दिल्ली,(ईएमएस)। लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में मॉनसून सत्र के दौरान हुए कामकाज का लेखा-जोखा रखा। सत्र स्थगित होने के उपरांत रखी गई अनौपचारिक चाय पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक-दूसरे का अभिवादन करते नजर आए।

लोकसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन स्थगित किए जाने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने मॉनसून सत्र के दौरान किए गए कामकाज का लेखा-जोखा रखा। उन्होंने सदन में पारित किए गए विधेयकों के साथ ही निजी संकल्प पर हुई चर्चा का भी जिक्र किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा, कि इस सत्र की प्रोडक्टिविटी 136 परसेंट रही है। सत्र स्थगित किए जाने के बाद ही एक अनौपचारिक चाय बैठक का इंतजाम किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक-दूसरे का अभिवादन किया और गर्मजोशी से नमस्कार करते दिखे। इस बीच राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के संबंध में पूछा, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इस पर अपनी कड़ी नजरें बनाए हुए है। इस चाय पार्टी की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी, स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल और चिराग पासवान आदि बैठे नजर आए हैं। गौरतलब है कि संसद के मॉनसून सत्र का 09 अगस्त शुक्रवार को 15वां दिन था। इसी दिन लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

वक्फ बिल के लिए जेपीसी का गठन

-31 सदस्यों वाली जेपीसी में 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से

नई दिल्ली(ईएमएस)। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दिन पहले लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) को भेज दिया गया था। स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि जल्द ही इसे लेकर जेपीसी बनाएंगे। अब इसे लेकर जेपीसी के 21 सदस्यों के नाम सामने आ गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में जेपीसी के 21 सदस्यों के नाम बताए। किरेन रिजिजू ने कहा कि 31 सदस्यों वाली इस जेपीसी में 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। किरेन रिजिजू ने कहा कि जेपीसी वक्फ बिल पर अगले सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने जेपीसी में लोकसभा के जिन 21 सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है, वह नाम भी बताए। नाम सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद के सुरेश ने एनके प्रेमचंद्रन को भी जेपीसी में शामिल करने की मांग की।

वक्फ बिल पर लोकसभा से जेपीसी में होंगे ये सदस्य

जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, श्रीमती डीके अरोड़ा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्ला, कल्याण बनर्जी, ए राजा, एलएस देवरायुलु, दिनेश्वर कामायत, अरविंत सावंत, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत मास्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार.....केंद्रीय मंत्री शाह ने गठित की कमेटी

-कंटीले तारों के उस पार.......हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू

कूचबिहार (ईएमएस)। बांग्लादेश में वर्तमान में उथल-पुथल मची हुई है। प्रदर्शनकारी वहां हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भारत-बांग्लादेश सीमा पर कूचबिहार जिले के कंटीले तारों के दूसरी ओर एकत्र हो गए हैं। हालात को देखकर इलाके में बीएसएफ की 157 बटालियन के जवानों को तैनात किया है। बता दें कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू कंटीले तारों से करीब 400 मीटर दूर गैबंडा जिले के गेंडुगुरी और दैखवा गांवों में जुटे हुए हैं। शुक्रवार सुबह से ही ये लोग खड़े हुए हैं। दूसरी ओर कूचबिहार में कंटीले तारों के पास शीतलकुची के पठानटुली गांव में पर्याप्त संख्या में बीएसएफ के जवान तैनात हैं और लगातार गश्त की जा रही है।

वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश में चल रही स्थिति के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति गठित की है।

प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा और यमुना का जलस्तर

प्रयागराज (ईएमएस)। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बीते चार-पांच दिनों से लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 271 सेंटीमीटर और छतनाग में 65 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि यमुना नदी का नैनी में जलस्तर 46 सेंटीमीटर बढ़ा है। कंट्रोल रूम से गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हजारों लोगों के घिरने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है।

बाढ़ का पानी अब झूंसी इलाके के बदरा सोनौटी सहित कई गांवों में प्रवेश कर गया है।

बारिश की वजह से प्रदेश भर में सात मौतें गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश से जुड़ी घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई। राज्य के नौ जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। बयान के मुताबिक, बालिया, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बिजनौर, वाराणसी, बांदा, बुलंदशहर, प्रयागराज और बाराबंकी अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। बिजली गिरने, डूबने, आग लगने और सांप के काटने से प्रतापगढ़ में तीन और श्रावस्ती में दो लोगों की मौत हुई, जबकि गाजियाबाद और चित्रकूट में से एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 271 सेंटीमीटर और छतनाग में 65 सेंटीमीटर बढ़ा है,

जन हितैषी

गिरफ्तारी और अदालती चक्रव्यूह से जनता को राहत जरूरी, न्याय के नाम पर अन्याय नहीं

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। 100 करोड रुपए के शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है। उन्हें ट्रायल कोर्ट से ईड़ी मामले में जमानत मिल चुकी है। ईड़ी के अधिकारी बिना आदेश के हाईकोर्ट पहुंच गए। वहां से ट्रायल कोर्ट के आदेश पर स्थगन प्राप्त कर लिया। इसके बाद से वह जेल में बंद है। जैसे ही सरकार को लगा, सुप्रीमकोर्ट के आदेश से अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो सकते हैं, उनकी रिहाई के पहले सीबीआई ने जेल से उनकी गिरफ्तारी कर ली। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने गलत मानते हुए निरस्त कर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। न्याय के नाम पर अन्याय का जो खेल खेला जा रहा है। लोकतांत्रिक देशों में सरकारों द्वारा अपने विपक्षियों को दबाने के लिए कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से विपक्षियों को राजनीति से दूर करने के लिए कानून के मकड़जाल में उलझाकर, अदालती चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है। कई महीनों और वर्षों तक गिरफ्तारी करके सत्ता से दूर रखा जाता है। सत्ता को चुनौती देने पर विपक्षियों पर न्याय के नाम पर अन्याय किया जा रहा है। अब इसके भीषण परिणाम देखने को मिलने लगे हैं। भारत के संविधान में जमानत को अधिकार माना गया है। अंग्रेजों के कानून में भी जमानत को अधिकार माना गया था। 90 दिन के अंदर यदि जांच एजेंसी ट्रायल शुरू नहीं करती थी, तो जमानत देने का अधिकार ट्रायल कोर्ट के पास था। जमानत लेने का अधिकार आरोपी का है। पिछले वर्षों में जो कानून बनाए गए हैं, उसमें आपातकाल से भी ज्यादा खराब प्रावधान कर दिए गए हैं। जिसके कारण नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। घोषित आपातकाल 18 महीने में खत्म हो गया था। कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए इसे कुछ समय के लिए लागू किया गया था। जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, सभी को जेल से रिहा कर दिया गया था। विपक्षी दलों ने भी चुनाव में भाग लिया था। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। अघोषित आपातकाल में अब राजनीतिक दलों के नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में कई महीनो और वर्षों तक जेलों में रखा जा रहा है। जांच एजेंसियां वर्षों तक जांच करती रहती हैं। 90 दिन के बाद ट्रायल भी शुरू नहीं होता है। जब बड़े-बड़े नेताओं को इस तरह से जेल भेजा जा रहा है। इसका असर अब देखने को मिल रहा है। जांच एजेंसियां जिनमे ईड़ी, सीबीआई और पुलिस, निरपराध लोगों के ऊपर गलत मामले बनाकर जेल भेज देती है। जेल भेजने की धमकी देकर कारोबारियों और आम जनता से वसूली का नया ट्रेंड भारत में शुरू हो गया है। ईड़ी, नारकोटिक्स, पुलिस और सीबीआई के कई अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। सरकार स्वयं जब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तब जांच एजेंसी भी निजी स्वार्थ के लिये अधिकारों का दुरूपयोग कर रही हैं। अब तो अदालतों के ऊपर भी रिश्वत के आरोप लगने लगे हैं। न्यायपालिका में भी यह बीमारी तेजी के साथ फैल गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब हाईकोर्ट के जज चुनौती देते हुए नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट और जांच एजेंसियों की मिली भगत से जमानत होने के बाद भी आरोपियों को अन्य मामलों में जेल में रखने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। न्यायपालिका में अनुशासनहीनता फैल चुकी है। जिस संविधान के नाम से सभी शपथ लेते हैं। उस संविधान की हत्या का दिवस सरकार 25 जून को घोषित करती है। ऐसी स्थिति में संविधान का चीर-हरण होना तय है। यह होता हुआ दिख भी रहा है। जिस न्यायपालिका को संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वह आंख बंद करके सरकार के पक्ष में काम करती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में आम नागरिकों की सुनवाई कहां और कैसे होगी। यह चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश में भी लगभग वही स्थिति बन गई थी, जो आज भारत में है। सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। बिना विपक्ष के चुनाव कराया गया था। विपक्ष को लंबे समय से जेल में बंद रखा गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। उन्हें बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा था। अब वह बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं। विपक्षी दलों के नेताओं को जेल से रिहा किया गया है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की हालत भी इससे इतर नहीं है। श्रीलंका में भी यही सब हुआ था। जब जब सरकारों में भ्रष्टाचार बढ़ता है। सत्ता में बैठे हुए लोग जब अहंकारी हो जाते हैं, तब यही स्थिति बनती है। कोई भी निरंकुश, अहंकारी, भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था लंबे समय तक चलने का कोई इतिहास नहीं है। जो भी तानाशाह बनता है, उसे जनता लोकप्रियता और अच्छे कामों के लिए सत्ता सौंपती है। सत्ता में लंबे समय तक रहने के कारण उसके आचरण में अहंकार और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ने लगते हैं। तानाशाहों के अंत का कारण भी उनका अहंकार होता हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका में यही हुआ है। भारत की जनता को यदि भ्रष्टाचार, अदालती चक्रव्यूह, गिरफ्तारियों, जमानत के कानून में राहत नहीं मिली, तो संविधान एवं लोकतंत्र को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होगा। सत्ता पक्ष ने 25 जून को संविधान का हत्या दिवस घोषित कर दिया है। इसका एक ही मतलब निकलता है, अब भारत में संविधान नामक कोई चीज नहीं है। इसका असर अब दिखने लगा है। जिनके पास अधिकार हैं, वह उसका दुरुपयोग अपने निजी हितों के लिए कर रहे हैं। जनता विरोध करने सड़कों पर उतरने लगी है।

कहाँ खड़े हैं तथाकथित अन्नदाता ?

समझने लायक कुछ तथ्य जिन पर हमे गौर करना होगा, जिनकी जानकारी होने से हम भली भांति समझ सकेंगे की आज हम किसानों की स्थिति मे दिन प्रति दिन इतना ह्रास क्यो हो रहा है ? ... आजादी के समय हम किसानों की आबादी 75इ थी अब रह गई 60इ ।

वर्तमान मे देश मे कुल किसानों की संख्या है 72 करोड़ ।इस वर्ष 2024 मे देश के कुल बजट की राशि है 48.21 लाख करोड़ रुपये।

कुल बजट मे कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के लिए इस वर्ष प्रावधान किया गया है 1.52 लाख करोड़ रुपये का। यानी हम 60इ की आबादी के लिए देश के कुल बजट मे प्रावधान है केवल .. 3.15 प्रतिशत । विगत वर्ष की तुलना मे बृद्धि केवल 0.4 प्रतिशत। इस वर्ष मे हमारी कृषि की लागत मे बृद्धि 10 इ से अधिक। कृषि की विकास दर विगत वर्षो मे घटते घटते 4.6 प्रतिशत से घट कर अब इस वर्ष रह गई केवल 1.8 प्रतिशत। कृषि शोध तीब्रता (ए आर आई) एवं कृषि जी डी पी का अनुपात विगत वर्षों मे 0.75 प्रतिशत से घटकर इस वर्ष रह गया 0.43 प्रतिशत। यदि हम केवल कृषि की बात करें (इससे सम्बद्ध क्षेत्र को छोड़ दें) तो 2021 मे कुल बजट मे प्रावधान था 4.47 प्रतिशत। पिछले वर्षो में और कम हुआ और कम होते होते अब इस वर्ष 2024 मे हो गया 2.48 प्रतिशत। यानी लगभग आधा !!..

हमारी खेती की लागत मे लगातार बृद्धि 10 से 15 प्रतिशत से अधिक की...

शासकीय एजेंसी एन एस एस ओ की रिपोर्ट के अनुसार किसान की प्रति दिन की आय केवल 27/- प्रति दिन है। विगत 5 सालों मे इसमे कोई बृद्धि नही हुई।.. बल्कि कई राज्यों मे घटी है। कृषि की स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसान की आय दुगनी होने की बजाय कई राज्यों मे उल्टा कम हुई है।...

पिछले 5 वर्षो मे सरकार ने बजट के प्रवधान का लगभग एक लाख करोड़ रुपये सरेंडर किये,यानी वह खर्च नही कर पाई।..

यानी कृषि के लिए कुल आबंटित बजट मे से मैंदान मे कितना खर्च हुआ हुआ यह अंदाज लगाना कठिन नही है, वह है लगभग 60 प्रतिशत। विडंबना है हमारी 30 से 40 प्रतिशत राशि लेप्स हो गई , हमारी सरकारें खर्च नहीं कर पाईं।

इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें...

सोर ऊर्जा की महत्वाकान्क्षी पी एम कुसुम योजना मे देश मे 10 लाख किसानों के यहाँ कृषि पम्प लगाने का प्रावधान था, जिसमे कुल स्वीकृत हुए 1,61,640 सोलर पम्प और लगाए गये केवल एक चौथाई किसानों के यहां।..

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर (कृषि संसाधन) के लिए विगत पांच वर्षो के लिए प्रावधान किया गया था एक लाख करोड़ खर्च करने का, उसमे से पांच सालों मे योजनाएं बनी केवल 35 हजार करोड़ रुपये खर्च की, परन्तु जारी हुए केवल 25 हजार करोड़ रुपये, यानी 10,00 करोड़ रुपये लेप्स।

इसी तरह हमारे बजट के प्रावधानो के बावजूद भी हमारे ऊपर खर्च कितने हुए अंदाज लगाया जा सकता है

इस वर्ष किसमे कितनी कटौती (कुछ बिंदु केवल उदाहरण के लिए समझें...

पी एम मान धन योजना के लिए विगत वर्ष प्रावधान था 138 करोड़ का, अब रह गया 100 करोड़।

हमारे देश के यूरिया मे इस वर्ष 2000 करोड़ की कटौती।

आयातीत यूरिया के लिए विगत वर्ष प्रावधान था 30 हजार करोड का , अब रह गया 22 हजार करोड़। इसमे भी 8 हजार करोड़ की कटौती।

हमारे देश मे निर्मित अन्य खादों के लिए पिछले वर्ष बजट था 32,370 करोड़, अब इस वर्ष रह गया 26,500 करोड़। 5870 की कटौती।

विदेशो से आयतित अन्य खादों के लिए भी इस वर्ष आवंटन मे 9430 करोड़ की कटौती की गई है।

फ़र्टिलाइजर की दी जाने वाली सब्सिडी मे इस वर्ष कटौती.. 25,711 करोड़ ।

पी एम फसल बीमा योजना मे इस वर्ष 400 करोड़ की कटौती कर दी गई। ..

पी एम फसल योजना मे सरकार ने जो प्रेमियम इकट्ठा किया, उसका किसानों मे बाँटा केवल आधा।

बीमा कंपनियों को विगत वर्षो मे फायदा..63,648 करोड़ का।

ग्रामीण मजदूरों के लिए मनरेगा के बजट मे भी कटौती।

कृषि शोध पर राशि मे भी कटौती, जबकी कृषि अर्थ शास्त्री मानते है की कृषि शोध पर एक रुपये खर्च करने पर 10 रुपये से अधिक का कृषि मे फायदा होता है।.... देश का कृषि अनुसंधान केंद्र कंगाली की कगार पर खड़ा है। वैज्ञानिको के आधे पद रिक्त पड़े हैं। सरकार के पास भर्ती के लिए फंड नही है।

अब आगे बात करें एम. एस. पी. की...

सरकार 24 फसलों की एम एस पी तय करती है, और खरीद होती है केवल 8, 10 फसलों की ही । ...

इसका कितना लाभ हमे मिलता है? कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करें। ...

गेहूँ का देश मे वर्ष 23- 24 मे कुल उत्पादन हुआ 1129 लाख मेट्रिक टन का, और खरीद हुई केवल 262 लाख मे. टन की। यानी खरीद केवल 23 प्रतिशत की ही ..

इसी प्रकार चने की खरीद 0.37 प्रतिशत ... मसूर की 14 प्रतिशत, सरसों की 9.19 प्रतिशत, सूरज मुखी एवं जो की 0 प्रतिशत हुई।..

शेष किसान ऑने पोने दाम मे बाजार मे बेचने मजबूर हुआ। ...

अब बात करें फसलों की लागत मूल्य की...

कृषि मूल्य आयोग ने नीति आयोग को प्रेषित एक रिपोर्ट मे स्वीकार किया है की किसानों की प्रांतों की लागत का मूल्यांकन सही नहीं है, प्रांतों मे फसल उत्पादन की लागत, समर्थन मूल्य से अधिक है। डॉ स्वामीनाथन के सी 2 पर 50 प्रतिशत के फार्मूले को न लेकर यदि उनके दूसरे फॉर्मूले ए 2 + एफ एल को ही लेवे तो सन 24-25 मे किसानों को धान मे प्रति हेक्टेयर 31.4 इ का नुकसान उठाना पड़ा। उड़द मे 475/-,सोयाबीन मे 4749/-, ज्वार मे 718/- प्रति हेक्टेयर का नुकसान सहना पड़ा, इसी प्रकार अन्य फसलों मे भी किसान घाटे मे खेती कर रहे हैं।...

जरा विचार कीजिये की इन परिस्थितियों मे किसान की समृद्धि की कल्पना करना या डिंडोरा, क्या बेमानी नही है ?? ...

विगत वर्षो मे मैंने नीति आयोग एवं कृषि मूल्य आयोग की कई बैठकों मे भाग लिया, वहाँ किसानों का पक्ष जोरदारी से रखने के प्रयास किये गये । विडंबना है की आर्थिक नीतियों पर अफसर शाही और उनकी अलग सोच, माइंड सेट, धारणाओं और मान्यताओ के चलते, हमें तो छोड़ दें, सरकार मे बैठे हमारे नुमाइंदे भी बेबस, असहाय नजर आते दिखते हैं। ..

कुल मिलाकर इन सबका आंकलन करने पर यह स्पस्ट समझ मे आता है की खेत - किसान न कभी किसी सरकार की प्राथमिकता मे रहा है और न रहेगा।..

दिन प्रति दिन गिरते इन आंकड़ों से स्पस्ट है की सरकार की नीति खेती के रकवे और किसानों की संख्या को कम करने की है।..और इसी नीति के तहत सरकार आगे बढ़ रही है।

यही कारण है की घाटे की खेती से आगे आने वाली पीढ़ी बच रही है। किसान इस धंधे से अलग हो रहे हैं। यही नहीं, देश मे कर्ज मे डूबे हर रोज 31 किसान आत्म हत्या करने मजबूर हो रहे हैं। इसकी पुष्ठी सरकार की रिपोर्ट करती है।

... इस पहलू को शायद हम समझ सकें। ...

सरकार शायद यह भूल रही है की अन्नदाता ने ही देश के अन्न के भंडारों को भरा, तभी तो करोना काल मे देश की आबादी का पेट भरने मे सरकार सफल हो पाई।... नहीं तो भुखमरी की एक अन्य त्रासदी से हमे गुजरना पड़ता।...

अगले पांच सालों तक 80 करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज की सुविधा के सरकार के वायदे का क्या होगा, यदि किसान खेती करना बंद कर दें ।...

हमेशा हमे यह कह कर दबाया जाता है की किसान से टेक्स नही लिया जाता, जबकी सच्चाई यह की हम अप्रत्यक्ष रूप से हर वस्तु पर टेक्स देते हैं, चाहे वह खाद हो, डीजल हो, यंत्र हों, आदान सामग्री हों। रोटी कपड़ा, मकान , रोज मर्रा की वस्तुएं हों, सबके टेक्स का भुगतान वह करता है। किसान का देश की आर्थिक उन्नति मे भी उतना ही योगदान है। ...

किसानों के द्वारा भरे गये अन्न के भण्डारों के कारण बड़ी बड़ी बातें !!... खाली पेट होते तो शायद इसमे कमी आती। भगवान् न करे वह स्थिति आये।...(लेखक - इंजी. के के अग्रवाल/ ईएमएस)

पडोसी देशों में भारत-विरोधी सरकारों के गठन की चिन्ता

भारत के पडोसी देशों में अस्थिरता एवं अराजकता का माहौल चिन्ताजनक है। बांग्लादेश के साथ-साथ भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुए हालिया अराजक, हिंसक एवं अस्थिरता के घटनाक्रमों से एक तस्वीर बनती है एवं एक सन्देश उभर कर आता है, वह है, चीनी के द्वारा भारत विरोधी सरकारों के गठन की साजिश। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल और तख्तापलट के बाद अस्तित्व में आई सरकारों ने भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर दिए हैं। भारत को सतर्क एवं सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल ये उठते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में हो रही इस अराजकता एवं अस्थिरता के कारण क्या हैं? यह सिर्फ एक संयोग है या फिर साजिश? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? क्या पाकिस्तान भी इसके लिये जिम्मेदार है? पड़ोसी देशों में पनप रही इस राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर होगा?

इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थितियां चीन और पाकिस्तान ने मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका में खड़ी की है।

हसीना का जाना या उनका निष्कासन चीन एवं पाकिस्तान की साजिशों का परिणाम है, जो भारत के लिए कई मायनों में झटका है। इसका यह मतलब भी है कि भारत ने पड़ोस में अपने इकलौते स्थिर साथी को अब खो दिया है। भारत अपने चारों ओर से बदहाल, कट्टरवादी, अराजक एवं अस्थिर पड़ोसियों से घिरा है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, जिस पर कट्टरपंथी तालिबान का राज है। भारत-विरोधी समूहों को समर्थन देने का उसका एक काला इतिहास रहा है। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन देश ही है। एक बेहद अशांत पड़ोस, जो कट्टरपंथियों, सैन्य शासकों, दिवालिया अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु-परिवर्तन के कारण डूबते देशों में अग्रणी है। अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद वह भारत विरोधी षडयंत्र रचता ही रहता है। वह राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय है। विडम्बना देखिये कि पाकिस्तान के एक भी वजीरे-आजम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हमेशा वहां की फौज ने उनके कार्यकाल में टांग डाली है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका 2022 में दिवालिया हो गया था। वहां से सामने आई तस्वीरें एवं घटनाक्रम आज के बांग्लादेश से काफी मिलती-जुलती रही हैं। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने बड़ा जनआंदोलन किया और जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिस कारण राष्ट्रपति गोटाबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा था। आर्थिक दिवालियेपन का शिकार यह देश चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। श्रीलंका के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चीन का था, जिस कारण चीन ने यहां के हंबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। हालात यह हो गए थे कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था।

मालदीव एक समय भारत का सहयोगी हुआ करता था। वहां की अर्थव्यवस्था चीन और भारत पर निर्भर है। हालांकि, मालदीव की भारत से नजदीकी हमेशा चीन को खटकती थी, जिस कारण उसने इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। धीरे-धीरे इस देश की माली हालत बुरी होने लगी, जिसके बाद यहां चीन समर्थक और इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी। पाकिस्तान एवं चीन के दबाव में उनके नए राष्ट्रपति के सुर बदले हुए हैं। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले चीन का ही दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने कई भारत विरोधी फैसले किए, जिसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी भी शामिल थी। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं।

नेपाल बीते कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता के दौरे से गुजर रहा है। हाल ही में यहां एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रो-भारत माने जाने वाली प्रचंड सरकार सत्ता से बाहर हो गई। अब यहां चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की सरकार है। ओली इससे पहले 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उस समय भारत और नेपाल के संबंध काफी तनावपूर्ण रहे थे। नेपाल में गत 16 वर्षों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। हालात इतने बदहाल हैं कि वहां पर कुछ लोग राजशाही को फिर से बहाल करना चाहते हैं। नेपाल में भी चीन ने जाल बिछा रखा है। चीन विस्तारवादी, अलोकतांत्रिक और अपने आस-पड़ोस के देशों के साथ धौंस-डपट करने वाला देश है। वह भारत के भूखंडों पर अपनी मिल्कियत जताता रहता है। भूटान में घरेलू राजनीति स्थिर है, लेकिन वह चीन के साथ सीमा-समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है, और यह भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण है।

भारतीय उपमहाद्वीप के मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को दुनिया चुपचाप सब देख रही है, वहीं भारत इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की घटनाओं का उस पर सीधा असर होगा। भारत शांति कायम रखने एवं पडोसी देशों से मित्रता कायम रखने के अपने संकल्पों एवं रणनीतियों के लिए इन देशों पर भरोसा नहीं कर सकता। हमारे इर्द-गिर्द मची उथलपुथल, अस्थिरता एवं अराजकता हमारे वैश्विक एजेंडे को भी बाधित करती है। भारत की आबादी 1.4 अरब है। उसके सभी पड़ोसियों की कुल आबादी 50 करोड़ है। अर्थव्यवस्था के साथ भी ऐसा ही है। भारत की जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर है। बाकी सब मिलाकर लगभग एक ट्रिलियन हैं। भारत समर्थ है, शक्ति सम्पन्न है, दुनिया की तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिये उसे अधिक बलों की तैनाती, अधिक रक्षा खर्च और सीमाओं पर अधिक बुनियादी ढांचों का निर्माण करना होगा। क्योंकि भारत के सभी पडोसी देशों पर चीन का दबदबा है और उसके दबाव में भारत के लिये कभी भी संकट बन सकते हैं।

बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता, विवेक एवं समझदारी सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पडोसी देशों में उत्पन्न हालातों पर समझ एवं संयम से कदम उठाती रही है। बांग्लादेश की तख्तापलट घटनाओं पर भी उसने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपनी बात रखी। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर सर्वसम्मति बनना जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है। ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पडोसी देशों में न मिलना ही उनकी अस्थिरता एवं अराजकता का बड़ा कारण है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति कतई नहीं बननी चाहिए कि जहां राजनीतिक दलों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ जायें कि फौज का दखल देना पड़े या पडोसी देश अपनी स्वार्थों की रोटियां सेंकने में सफल हो जाये। भारत के पडोसी देशों के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी।

इन पडोसी देशों के नेता दो तरह के हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करें तो सभी पडोसी देश मिलकर विश्व में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इन पडोसी देशों के स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के केनवास पर शांति, प्रेम, विकास और सह-अस्तित्व के रंग भरने की अपेक्षा है। भारत इस स्थिति में है, उसे मनोबल के साथ पडोसी देशों में स्थिरता, शांति, लोकतंत्र एवं आपसी समझ की ज्योत जलाने के लिये तत्पर रहना चाहिए, जो उन देशों के साथ भारत के लिये भी जरूरी है।

(लेखक - ललित गर्ग/ईएमएस)
(खक, पत्रकार, स्तंभकार)

चर्चा में महामहिम... और अब 'लाटसाहब' के पद पर विवाद...?

जिस तरह हमारे संविधान के तहत महामहिम राष्ट्रपति जी को देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख माना गया है, उसी की तर्ज पर महा महिम राज्यपालों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख बताया गया है, इसीलिए राज्यपालों की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा केन्द्र की अनुशंसा पर की जाती है, हमारे संविधान में इस पद की योग्यता को लेकर भी स्पष्ट उल्लेख है, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक व अन्य क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त विद्वान को इस पद पर नियुक्ति का प्रावधान है, किंतु आजादी की हीरक जयंति के इस वर्ष में विद्वतजनों में यही चर्चा का विषय है कि आज के दौर में जो राज्यपाल नियुक्ति किए जा रहे है, वे पद की इस प्रमुख योग्यता की पात्रता रखते है? या राज्य के इस प्रमुख संवैधानिक पद पर भी राजनीतिक चौला चढ़ा दिया गया है और राष्ट्रपति के संरक्षण में रहने वाले राज्यपाल अब केन्द्र की राजनीतिक 'दया दृष्टि' पर निर्भर हो गए है, अर्थात केन्द्र पर राज करने वाला राजनीतिक दल व उसके नेता ही राज्यप्रमुख के 'माई-बाप' हो गए है।

हमारे संविधान में राज्यपाल के पद का सम्मिश्रण इसलिए किया गया था कि वह राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार पर संवैधानिक निगरानी रखे और समय-समय पर राष्ट्रपति जी को राज्य की हर गतिविधि से अवगत रखे। किंतु आज क्या हो रहा है? राज्यपालों के संरक्षक अब राष्ट्रपति जी नही बल्कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के राजनेता हो गए है और राज्य के संवैधानिक इस प्रमुख पद पर उन गए गुजरे तथा वयोवृद्ध राजनेताओं की नियुक्ति हो रही है, जो या तो चुनावों में जनता द्वारा कई बार ठुकरा दिए गए हो, या फिर जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल व नेताओं की सेवा सुश्रुषा में विशेष योग्यता प्राप्त हो, फिर चाहे उन्हें संविधान का ज्ञान हो या नहीं? यह जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें तो अपने अधिनस्थ अफसरों व केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के प्रादेशिक व राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व ने काम करना है?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक माननीया न्यायाधीश जस्टिस नागरत्ना ने भी महामहिमों की मौजूदा कर्तव्य निष्ठा पर यही सवाल उठाया है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ''कुछ राज्यपाल ऐसा काम कर रहे है, जो उन्हें नही करना चाहिए'' उनका स्पष्ट कहना था कि- ''आज राज्यपाल वहां भूमिका निभा रहे है, जहां उन्हें विवादित भूमिका नहीं निभानी चाहिए, जहां उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी होती है, वहां वे निष्क्रीय हो जाते है, उनका स्पष्ट कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों की खिलाफ मामले देश में राज्यपाल की संवैधानिक दशा की दुःखद कहानी है।'' वैसे नागरत्ना जी ने अपना यह वक्तव्य किसी राज्य विशेष के राज्यपाल को लेकर नही दिया, किंतु चर्चा है कि उनका स्पष्ट संकेत कर्नाटक के राज्यपाल को मध्यप्रदेश के वरिष्ठ राजनेता थावर चंद गेहलोत को लेकर थी, जिनकी वहां की कांग्रेस राज्य सरकार से कथित अनबन चल रही है, जिसका विषय मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण है तथा जमीन आवंटन के नाम पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को कथित तौर पर रिश्वत देने का आरोप है। राज्यपाल गेहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या को कारण बताओं नोटिस दिया था, जिस पर राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल से अपना नोटिस वापस लेने की मांग की है।

यह तो महज एक उदाहरण मात्र है, वैसे देश के एक दर्जन से भी अधिक राज्यों में राज्यपाल व वहां की सरकारों के बीच अर्न्तद्वन्द जारी है, विशेषकर उन राज्यों में जहां राज्य सरकार को सत्तारूढ़ दल विरोधी दलों के राज्यपाल तैनात है।

इस तरह कुल मिलाकर आज सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि क्या मौजूदा राज्यपालगण अपने दायित्वों, कर्तव्यों का निर्वाहन संवैधानिक दायरें में कर रहे है? या राज्यपाल का पद अब अर्थहीन हो गया है? शायद इसीलिए कुछ समय पूर्व संवैधानिक विद्वानों द्वारा इस पद को खत्म करने की मांग की गई थी? (लेखक- ओमप्रकाश मेहता / ईएमएस)

शब्द पहेली - 8094

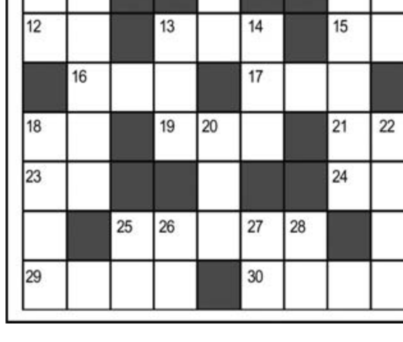

बाएँ से दाएँ

1. दुर्व्यवहार, बुरा आचरण-4
4. पंजाब की एक नदी-4
7. अनाथालय-5
9. दूसरा, पराया-2
11. चलने का तरीका-2
12. नृत्य-2
13. समीप, पास, नजदीक-3
15. बुरी आदत-2
16. नृत्य करना-3
17. प्रलोभन, हवस, तृष्णा-3
18. मालिक, ईश्वर-2
19. निहित, कारण-3
21. भाग्य(अंग्रेजी-2)
23. थूक, लेस-2
24. नवीन, नव-2
25. नयापन, अनूठापन-5
29. नामवाला, नामचिन-4
30. करिश्मा, चमत्कार-4

ऊपर से नीचे

1. मनोरचना, मनगढ़ंत-4
2. कोक, कहवा-2
3. कामदेव की पत्नी-2
4. मित्र, दोस्त-2
5. पेड़ का मध्य भाग-2
6. नादानी, अनाड़ीपन-4
8. बंदर नचाने वाला-3
10. रचना करने वाला-5
11. आरचण, चरित्र-5
13. कपड़े की दिवार-3
14. उठा ले जाना, बलपूर्वक-3
18. पूजा, प्रार्थना-4
20. खूबसुरत, सुन्दर-3
22. कहर, भूचाल-4
25. नया, नवीन-2
26. शूर, बहादुर, सूरमा-2
27. अवधि में, पर्यंत-2
28. मृत, अप्रबल-2

शब्द पहेली -8093 का हल

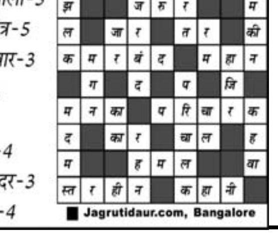

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद बरकरार

खेल कोर्ट ने कहा-ओलिंपिक खत्म होने पर करेंगे फैसला; भारतीय वकील ने फाइनल खेलने का चांस मांगा

पानीपत(ईएमएस)। पेरिस ओलिंपिक में फाइनल से ठीक पहले ओवरवेट बता अयोग्य करार दी गईं विनेश फोगाट की याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सुनवाई चल रही है। भारत की ओर से एडवोकेट हरीश सॉल्वे ने पक्ष रखते हुए कहा कि विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए या उसे फाइनल खेलने का चांस मिले।

इस पर कोर्ट ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से रेसलिंग को लेकर नियम पूछे। इसके बाद ष्ट्रस् ने कहा कि पेरिस ओलिंपिक की समाप्ति से पहले विनेश फोगाट की याचिका पर फैसला आने की उम्मीद है। फोगाट ने बुधवार को अपनी अपील दायर की और नए वेट-इन की मांग करते हुए फाइनल में भाग लेने की अनुमति मांगी। सुनवाई की प्रक्रिया के लिए बहुत कम समय था।

उधर, विनेश ने ष्ट्रस् में अपील दायर करके मांग की थी कि 50यत्र वेट कैटेगरी में उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। इसके बाद उनकी ये अपील स्वीकार कर ली गई थी। ओलिंपिक से डिसक्वालीफाई होने पर विनेश फोगाट संन्यास ले चुकीं हैं। बीते कल उन्होंने सोशल मीडिया (ङ्ग) पर इसका ऐलान किया।

भारतीय पुरुष रिले टीम पेरिस ओलंपिक से बाहर हुई

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय पुरुषों की चार गुण 400 मीटर रिले टीम पेरिस ओलंपिक में खराब प्रदर्शन के साथ ही बाहर हो गयी है। भारतीय टीम शुरुआती हीट में 10वें स्थान पर रहने के कारण अंतिम दौर में नहीं पहुंच पायी।

भारत के मोहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल, अमोज जैकब और राजेश रमेश ने हालांकि सत्र का सर्वश्रेष्ठ समय तीन मिनट और 0.58 सेकंड निकाला पर दूसरी हीट में वह सातवें स्थान पर रहे जिससे उसे 16 टीमों में से कुल मिलाकर 10वां स्थान ही मिल पाया। दोनों हीट में से शीर्ष तीन टीम तथा दोनों हीट में अगली दो सबसे तेज टीमें फाइनल दौर में पहुंचती हैं।

वहीं बोत्सवाना की टीम 2:57.76 का समय निकालकर पहले जबकि ब्रिटेन की 2:58.88 का समय निकलकर दूसरे व अमेरिका की टीम 2:59.15 का समय निकालकर तीसरे नंबर पर रही। जापान की टीम 2:59.48 के समय के साथ ही चौथे स्थान पर रही। वहीं महिलाओं की चार गुणा 400 मीटर रिले टीम भी पहले दौर की हीट में भाग लेने वाले 16 देशों में 15वें स्थान पर रहने के बाद बाहर हो गयी थी। विथ्या रामराज, ज्योतिका श्री दांडी, एमआर पूवम्मा और सुभा वेंकटेशन की चौकड़ी ने 3:32.51 का समय निकाला और हीट नंबर दो में आठवें और आखिरी स्थान से कुल 15वें स्थान पर रही।

हॉकी इंडिया ने कांस्य पर खुशी जताते हुए इनाम घोषित किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने पर खुशी जताते हुए कहा है कि टीम के सभी सदस्यों को 15-15 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। भारतीय टीम ने यहां तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराया।

हॉकी इंडिया ने सोशल मीडिया में लिखा ,'' हॉकी इंडिया पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रूपये जबकि सहयोगी स्टाफ को साढे सात लाख रूपये का पुरस्कार देगा।

भारतीय टीम ने लगाता दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। पिछले बार हुए टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय टीम ने कांस्य जीता था। इसी के साथ ही ओलंपिक में ये भारतीय हॉकी टीम का 13वां पदक है। भारतीय टीम ने ओलंपिक में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हराया था जबकि बेल्जियम से उसका मुकाबला बराबरी पर रहा था।

रोहिदास को 4 करोड़ का इनाम देगी ओडिशा सरकार,प्रत्येक खिलाड़ी को मिलेंगे 15-15 लाख रुपए

पेरिस (ईएमएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी अमित रोहिदास को चार करोड़ रुपये इनाम देने की घोषणा की है। माझी ने पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई देते हुए टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। भारत ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है।

माझी ने ये भी कहा कि टीम के कर्मचारियों को भी 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा की ओर से खेलने वाले अमित रोहिदास को 4 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। माझी ने कहा कि आने वाले पीढ़ी इस जीत को याद रखेगी। इसलिए मैं रोहिदास और अन्य सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं, और मैं यह भी घोषणा करता हूं कि सभी खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए और स्टाफ को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।

वहीं ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम से बात कर उसे बधाई दी। पटनायक ने कहा, ओडिशा और पूरे भारत की ओर से भारतीय टीम को बहुत-बहुत बधाई, हमें आप पर बहुत गर्व है। आपने शानदर प्रदर्शन किया है। वहीं अपना अंतिम मैच खेल रहे श्रीजेश को इस मैच में जीत के साथ ही विदायी मिली है।

पेरिस ओलंपिक में सौ से अधिक पदक जीतकर अमेरिका नंबर एक पर कायम भारत 64 वें स्थान पर खिसका

पेरिस (ईएमएस)। पेरिस ओलंपिक में अमेरिका ने अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक पदक जीतकर पहला स्थान बनाये रखा है। वहीं चीन 73 पदकों के साथ दूसरे जबकि ऑस्ट्रेलिया 45 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं मेजबान फ्रांस 54 पदकों के साथ ही चौथे स्थान पर है। ब्रिटेन 51 पदकों के साथ पांचवें नंबर पर है। भारत केवल 5 पदक लेकर 64 वें स्थान पर है। भारत के पांच पदकों में से दो तीन पदक शूटिंग जबकि एक- हॉकी और एथलेटिक्स में आये हैं।

अमेरिका 30 स्वर्ण सहित कुल 103 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं चीन 29 स्वर्ण के साथ ही कुल 73 पदक लेकर दूसरे जबकि ऑस्ट्रेलिया 18 के साथ ही कुल 45 पदकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर है जबकि फ्रांस और ब्रिटेन 14 और 13 स्वर्ण सहित कुल 54 और 51 पदक लेकर चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

भारतीय टीम अब एक माह आराम के बाद बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी

मुम्बई (ईएमएम)। भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका दौरा समाप्त हो गया है। हस दौरे में भारतीय टीम को जहां टी20 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 3-0 से जीत मिली थी। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में एकदिवसीय सीरीज में उसे हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम को श्रीलंका में 27 साल के बाद किसी एकदिवसीय सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। अब भारतीय टीम

को करीब एक माह से अधिक का ब्रेक मिला है। टीम अब अपना अगला मैच 19 सितंबर को बांग्लादेश से अपनी ही धरती पर खेलेगी हालांकि जिस प्रकार के हालात बांग्लादेश में है उसमें उसके भारत दौरे पर आशंकाएं भी लगायी जा रही हैं। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट चेन्नई में 19 सितंबर से शुरु होगा जबकि दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कानपुर में होगा। टेस्ट सीरीज के बाद भारत श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 मैच खेलेगा। बांग्लादेश सीरीज के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से खेलना है। कीवी टीम 24 अक्टूबर से 8 नवंबर तक होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरे पर आयेगी। टेस्ट सीरीज के बाद, भारत चार मैचों की टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएगा। ये सीरीज 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच खेली जाएगी।

भारतीय रेसलर अमन सहरावत पेरिस ओलिंपिक में 57 किलोग्राम का सेमीफाइनल मैच हारे

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय रेसलर अमन सहरावत पेरिस ओलिंपिक में 57 किलोग्राम का सेमीफाइनल मैच हार गए हैं। उन्हें जापान के रे हिगुची ने 10-0 से हराया। अमन अब शुक्रवार को ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे।

अमन ने क्वार्टर फाइनल में अल्बेनिया के जेलिमखान अबकारोव को 12-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं, अंशु मलिक विमेंस 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गईं। उन्हें अमेरिका की हेलेन लुईस मारौलिस ने 7-2 से हराया।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आया है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 819.69 अंक बढ़कर 79,705.91 अंक पर जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 250.50 अंक ऊपर आकर 24,367.50 अंक पर बंद हुआ। इस सप्ताह की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई थी, जिसकी वजह अमेरिका में बेरोजगारी दरों में आई गिरावट और बैंक ऑफ जापान की तरफ से ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी थी पर अब फिर से बाजार में सुधार आया है। इससे सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों हरे निशान में बंद हुए।

वहीं आज सुबह से ही बाजार की अच्छी शुरुआत हुई। इसका कारण अमेरिकी बाजार में सुधार के साथ ही निवेशकों के मन में मंदी की आशंकाएं कम होना है।

आज निफ्टी के सबसे अधिक लाभ वाले शेयरों में वाहन कंपनियों के शेयर रहे। आयशर मोटर्स के शेयर आज 5.68 फीसदी ऊपर आये और ये नंबर एक पर पहुंच गया। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.05 फीसदी, श्रीराम फाइनेंस 2.88 फीसदी, टाटा मोटर्स 2.81फीसदी और टेक महिंद्रा के शेयर भी 2.63फीसदी बढ़े।

दूसरी ओर नुकसान वाले शेयरों में एचडीएफसी लाइफ सबसे ऊपर रहा। उसके शेयरों में आज 1.09 फीसदी की गिरावट रही जबकि कोटक बैंक 0.16 फीसदी, मारुति सुजूकी इंडिया 0.12 और सन फार्मा 0.10 के शेयर भी सबसे अधिक नुकसान वाले शेयर रहें। निफ्टी के 50 शेयरों में सिर्फ यहीं चार शेयर ऐसे थे, जो आज गिरावट पर बंद हुए। वहीं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में, टोक्यो, सियोल और हांगकांग के शेयर ऊपर आये जबकि शंघाई नीचे आया। वहीं यूरोपीय बाजार से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। गत दिवस अमेरिकी बाजार काफी बढ़त पर बंद हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गत दिवस 2,626.73 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची।

वहीं आज सुबह बाजार तेजी के साथ खुला। बेंचमार्क सेंसेक्स 789 अंक उछलकर 79,675 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी50 235 अंक बढ़कर 24,352 के स्तर पर आ गया। बीएसई सेंसेक्स के सभी शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। खासकर, आईटी सेक्टर शानदार प्रदर्शन करते दिखे। टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसे प्रमुख आईटी शेयरों में 2 फीसदी तक की बढ़त रही।

डेलीगेटेड पेमेंटे सर्विस....अब आपके खाते से दूसरा यूजर कर सकता हैं पेंमेट

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट लगातार बढ़ा है, खासकर यूपीआई से भुगतान में तेजी आई है। इसलिए यूजर्स अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आरबीआई लगातार डिजिटल पेमेंट सिस्टम में नई-नई सुविधाएं लेकर आ रहा है। इसी कड़ी में आरबीआई ने डेलीगेटेड भुगतान सर्विस शुरु की। डेलीगेटेड पेमेंटे सर्विस से मतलब है कि यूपीआई यूजर अपने अकाउंट से पेमेंट करने का अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को दे सकेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी।

यूपीआई पेमेंट को लेकर डेलिगेटेड पेमेंट सर्विस में इसमें एक व्यक्ति (प्राइमरी यूजर) किसी अन्य व्यक्ति (सेकेंडरी यूजर) को अपने बैंक खाते से यूपीआई लेनदेन करने की अनुमति दे सकेगा। हालांकि, इसतरह के ट्रांजेक्शन की लिमिट प्राइमरी यूजर के द्वारा निर्धारित की जाएगी। इससे देशभर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस संबंध में भी विस्तृत निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगें।

थर्ड पार्टी पेमेंट एप कीवी के को-फाउंडर मोहित बेदी ने डेलिगेटेड पेमेंट सर्विस को लेकर कहा, इस कदम के जरिए आरबीआई प्राइमरी अकाउंट होल्डर (माता-पिता) को वह सुविधा देने जा रहे हैं, जिससे नाबालिग भ

सीबीडीटी आयकर बकाये की वसूली के लिए अभियान शुरू करेगा

मुंबई (ईएमएस)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है ?कि वह लंबित आयकर बकाये की वसूली के लिए अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने सितंबर के आ?खिर तक ऐसे 5,000 बड़े मामलों की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम का गठन करेगा। ये मामले कुल बकाया करों के लगभग 60 फीसदी हिस्से के लिए जिम्मेदार होंगे। यह कार्रवाई सीबीडीटी की केंद्रीय कार्ययोजना का हिस्सा है, जिसमें अधिकारियों को पुराने कर मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में सीबीडीटी ने जोर दिया है कि पिछली कर मांगों को निपटाने के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है और इसके लिए लक्ष्यों को तय किया गया है। इन मामलों में करदाताओं को पहले ही नोटिस भेजे जा चुके हैं लेकिन विभिन्न कारणों से अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। कानूनी मुकदमे, कंपनियों का बंद होना, करदाताओं का पता नहीं लग पाना और स्त्रोत पर कर कटौती में विसंगतियों के कारण ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा कुछ मामलों पर अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा रोक लगाने का आदेश भी दिया गया है। 1 अप्रैल तक लंबित कर बकाया 43 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि 1 अप्रैल, 2023 में यह 24 लाख करोड़ रुपए था। सीबीडीटी ने अपनी कार्ययोजना में इसे अत्यधिक वृद्धि बताते हुए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

लगातार कही जा रही मंदी आने की बात सच नहीं!

नई दिल्ली (ईएमएस)। लगातार आ रहीं मंदी आने की बात अभी सच होती नहीं ?दिखाई दे रही है। मंदी आने की मुख्य वजह नौकरियों का जाना होता है लेकिन अमेरिका से सामने आए ये आंकड़े अलग कहानी बता रहे हैं। दरअसल, यूएस में बेरोजगारी भत्ते के लिए दिए साप्ताहिक आवेदनों में गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 3 अगस्त के खत्म हुए सप्ताह के लिए बेराजगारी भत्ते के 2,33,000 दावे मिले जो साप्ताहिक आधार पर 17000 दावे कम है। इस बात की घोषणा यूएस के श्रम ?विभाग ने की है। इसे 11 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट बताया जा रहा है। जून के बाद से ही बेरोजगारी भत्ते के लिए दावे लगातार बढ़े हुए ही दिख रहे थे। हालांकि, छंटनी इस दौरान कम दिख रही थीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून में जो छंटनी हुई वह पिछले 2 साल के मुकाबले सबसे कम थीं। रॉयटर्स के अनुसार लेबर मार्केट में स्लोडाउन के पीछे छंटनी नहीं कंपनियों द्वारा हायरिंग को धीमा कर देना बड़ी वजह है। दिलचस्प है कि एक अन्य सरकारी के आकंड़े के अनुसार जुलाई में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.3 फीसदी पर पहुंच गई।

मुद्रास्फीति पर घरेलू औसत प्रत्याशा बढ़कर 8.2 प्रतिशत हुईः आरबीआई

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि जुलाई में किए गए ताजा सर्वेक्षण में मुद्रास्फीति पर घरेलू औसत प्रत्याशा बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गई। आरबीआई ने सर्वेक्षण के नतीजों के बारे में कहा ?कि ताजा सर्वेक्षण दौर में मौजूदा मुद्रास्फीति के बारे में घरेलू औसत प्रत्याशा 0.20 प्रतिशत बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गई। सर्वेक्षण के मुताबिक तीन महीने और एक साल आगे की अवधि के लिए मुद्रास्फीति की प्रत्याशा भी 0.20 प्रतिशत बढ़ी हैं। इस साल दो से 11 जुलाई के बीच किए गए सर्वेक्षण में 19 प्रमुख शहरों के कुल 6,091 प्रतिभागी शामिल हुए। सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि मई, 2024 के सर्वेक्षण दौर की तुलना में घरेलू क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा उच्च सामान्य कीमतों और मुद्रास्फीति की उम्मीद कर रहा है।

फिर सस्ता हुआ सोना, चांदी हुई महंगी

- सोना 69,600 रुपए, चांदी लगभग 80,750 रुपए

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोने के वायदा भाव की शुरुआत शुक्रवार को गिरावट के साथ हुई, जबकि चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। सोने के वायदा भाव 69,600 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 80,750 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सोने व चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। लेकिन सोना के भाव बाद में सुस्त पड़ गए। सोने के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रेक्ट 234 रुपये की गिरावट के साथ 69,470 रुपये के भाव पर खुला। इसके बाद यह 92 रुपये की गिरावट के साथ 69,612 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रेक्ट 71 रुपये की तेजी के साथ 80,686 रुपये पर खुला। इसके बाद यह 142 रुपये की तेजी के साथ 80,755 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने व चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। लेकिन बाद में सोने के भाव लुढ़क गए। कॉमेक्स पर सोना 2,467.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,463.30 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 3.60 डॉलर की गिरावट के साथ 2,459.70 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 27.64 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 27.60 डॉलर था। इस समय यह 0.06 डॉलर की तेजी के साथ 27.66 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

देश के बियरेबल उपकरणों की शिपमेंट में बड़ी गिरावट

- जून 2024 की तिमाही में 10 प्रतिशत घटकर 29.5 मिलियन यूनिट रह गई

नई दिल्ली (ईएमएस)। एक मार्केट रिसर्च फर्म ने कहा कि भारत में वियरेबल उपकरणों की शिपमेंट में पहली बार गिरावट दर्ज की गई, जो जून 2024 की तिमाही में 10 प्रतिशत घटकर 29.5 मिलियन यूनिट रह गई। पुराने मॉडलों के बड़े स्टॉक की ?बिक्री नहीं होने और इस सेगमेंट में नवाचार के निचले स्तर से ऐसा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार वनप्लस के साथ ओप्पो में साल दर साल 35.8 प्रतिशत की शिपमेंट में सबसे बड़ी गिरावट आई। इसके बाद फायर-बोल्ट का स्थान रहा, जिसके पहनने योग्य उपकरणों की शिपमेंट में 24.3 प्रतिशत की गिरावट आई, नॉइज़ में 13.9 प्रतिशत की गिरावट आई और बोट में साल दर साल 9.8 प्रतिशत की गिरावट आई। प्रमुख पांच ब्रांडों में बोल्ट एकमात्र खिलाड़ी था, जिसने शिपमेंट में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कुल शिपमेंट में गिरावट के बावजूद, बोट ने 26.7 प्रतिशत शेयर के साथ वियरेबल सेगमेंट का नेतृत्व किया, इसके बाद नॉइज (नेक्सबेस) ने 13 प्रतिशत शेयर, बौल्ट ने 8.1 प्रतिशत, फायर-बोल्ट ने 8 प्रतिशत, ओप्पो (वनप्लस के साथ संयुक्त) ने 7.6 प्रतिशत शेयर हासिल किए। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि त्योहारों के मौसम की शुरुआत से पहले पुराने स्टॉक को साफ करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विक्रेताओं द्वारा सावधानीपूर्वक इन्वेंट्री स्टॉकिंग और कम नए लॉन्च इस गिरावट के प्रमुख कारण थे। समग्र वियरेबल्स के लिए औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) भी 21 अमेरिकी डॉलर (1,763 रुपये) से 18.8 अमेरिकी डॉलर (लगभग 1,580 रुपये) के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। कुल शिपमेंट में गिरावट स्मार्टवॉच के शिपमेंट में 27.4 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुई, जो एक साल पहले 12.77 मिलियन से रिपोर्ट की गई तिमाही के दौरान 9.27 मिलियन हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है ?कि इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए कीमतों में कटौती और ब्रैंड्स द्वारा छूट दिए जाने के कारण स्मार्टवॉच एएसपी एक साल पहले के 25.6 डॉलर से गिरकर 20.6 डॉलर पर आ गया। एडवांस्ड स्मार्टवॉचा में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बाजार हिस्सेदारी 1.5 से बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गई। स्मार्टफोन सेगमेंट में सबसे ज्यादा नुकसान बोट को हुआ, जिसकी शिपमेंट में सालाना आधार पर करीब 45 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके बाद नोइज का स्थान रहा, जिसकी शिपमेंट में 32.4 प्रतिशत, फायर बोल्ट का 26.1 प्रतिशत और बोल्ट का 16.6 प्रतिशत की गिरावट आई। टाइटन एकमात्र ऐसा ब्रैंड रहा, जिसने स्मार्टफोन शिपमेंट में करीब 69 प्रतिशत की उछाल दर्ज की।

मनु और श्रीजेश होंगे पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक

पेरिस (ईएमएस)। पेरिस ओलंपिक खेलों का समापन 11 अगस्त को होगा। इसमें भारत की ओर से महिला वर्ग में मनु भाकर को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। वहीं पुरुष वर्ग से स्टार हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ध्वजवाहक रहेंगे। मुन ने इस बार ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतकर एक रिकार्ड बनाया है। वह एक ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। वहीं गोलकीपर श्रीजेश ने भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम के कांस्य पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई। श्रीजेश ने टूर्नामेंट के दौरान कई गोल रोके और भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान दिया। प्रेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का अभियान समाप्त होने के साथ ही श्रीजेश ने खेल से संन्यास भी ले लिया है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने मनु के साथ ही श्रीजेश को समापन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया है।

आईओए ने अपने एक बयान में कहा, भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर के साथ ही संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में श्रीजेश के नाम की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। वहीं आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि श्रीजेश आईओए नेतृत्व के अंदर एक भावनात्मक और लोकप्रिय विकल्प थे, जिसमें शेफ डी मिशन गगन नारंग और संपूर्ण भारतीय दल शामिल था। उषा ने कहा, श्रीजेश ने दो दशकों से अधिक समय तक विशेष रूप से भारतीय हॉकी और सामान्य रूप से भारतीय खेल में अहम भूमिका निभाई है।

'तिलक और 'बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? - मुस्लिम छात्रों के लिए 'ड्रेस कोड को लेकर उत्पन्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के प्राइवेट कॉलेज के सर्कुलर पर आंशिक रूप से रोक लगाते हुए कहा कि छात्राओं को यह चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह क्या पहनें। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि शैक्षिक संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद को नहीं थोप सकते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 'एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज चलाने वाली 'चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया और 18 नवंबर तक उससे जवाब तलब किया है। पीठ ने मुस्लिम छात्रों के लिए 'ड्रेस कोड को लेकर उत्पन्न नये विवाद के केंद्र में आए कॉलेज प्रशासन से कहा, ''छात्राओं को यह चयन करने की आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहनें और कॉलेज उन पर दबाव नहीं डाल सकता।।। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं।

पीठ ने कहा कि अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाना था, तो उसने 'तिलक और 'बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? न्यायालय ने एजुकेशनल सोसायटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान से पूछा कि क्या छात्रों के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होती? हालांकि, पीठ ने कहा कि छात्राओं को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि उसके अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी दुरुपयोग के मामले में 'एजुकेशनल सोसायटी और कॉलेज को अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में उत्तरप्रदेश को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली (ईएमएस)। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को लोकसभा में बहस के दौरान उत्तरप्रदेश को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा है, जिससे हर इलाके का सही तरीके से विकास हो सके। हालांकि भाजपा और समाजवादी पार्टी को उनकी यह मांग पसंद नहीं आई है।

चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर कहा कि यह प्रदेश का बंटवारा नहीं बल्कि इससे विकास के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसे एक राष्ट्र कह सकते हैं। 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। मेरा यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। बाबासाहेब भी यही कहते थे कि राज्य जितना छोटा होगा, उसका उतना ही उसका विकास होगा, उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा।

चंद्रशेखर ने एक समाचार चैनल को बताया कि आज भी हमारे लोगों को हाईकोर्ट के लिए करीब 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आज विकास का लाभ हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है। अधिकारी भी हर जगह नहीं जा पाते हैं। हालांकि चंद्रशेखर की इस मांग का बीजेपी और समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर का कहना है कि मैं जनता के लिए काम करता हूं। दूसरी पार्टियां क्या कहती हैं और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

ईरान चारों तरफ से इजराइल पर कभी भी कर सकता है हमला, सहमी दुनिया - यमन के हूती विद्रोही ईराक के रास्ते सीरिया पहुंचे

तेहरान,(ईएमएस)। हमास चीफ की मौत के बाद ईरान और उसके सहयोगियों ने इजराइल पर हमले की चेतावनी दी है। इसको लेकर पूरी दुनिया सकते हैं कि कहीं यह जंग और ज्यादा ना फैल जाए लेकिन ईरान किस तरह से इजरायल पर हमला करेगा? कहां से करेगा? कैसे करेगा? क्या रणनीति होगी? क्योंकि निशाना है इजरायल जिसे अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है।

अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक विमानवाहक युद्धपोत को इजरायल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट से उड़ान भरता एफ-ए-18 ई सुपर हॉरनेट फाइटर जेट। ईरान-इजरायल की वजह से मिडिल-ईस्ट में किसी भी समय जंग का बिगुल फूंक सकता है। इस बात की पूरी दुनिया को चिंता है। दुनिया की सभी ताकतवर शक्तियों को भी यह एक क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली भयानक जंग हो सकती है। आशंका है कि ईरान अपने समर्थक देशों के साथ मिलकर इजरायल पर चारों तरफ से हमला कर सकता है जहां वैश्विक कूटनीतिक समुदाय इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहा है। वहीं, सवाल उठ रहा है कि छोटा सा देश इजरायल कैसे ईरान के गुस्से का सामना करेगा? क्योंकि उसके साथ सीरिया, ईराक, फिलिस्तीन और यमन में मौजूद आतंकी समूह भी हैं। ये भी ईरान के साथ मिलकर इजरायल पर हमला बालेंगे।

इजरायल और उसका सबसे बड़ा समर्थक देश अमेरिका बड़े पैमाने की जंग की तैयारी कर रहे हैं। इजरायल ने हमास के कई बड़े लीडर्स को मार दिया है। सबसे बड़ा लीडर पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र दस दिन के अंदर मारे गए हैं।

इसके पहले ईरान ने इजरायल पर 330 ड्रोन और मिसाइल हमला किया जिसमें 13 लोग मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगला अटैक अप्रैल से ज्यादा खतरनाक होगा. डूम्स-डे नजदीक आ रहा है. ईरान तीन तरह से हमला करने की फिराक में है या कर सकता है इससे इजरायल पर घातक हमला तो होगा ही लेकिन अमेरिका से सीधे पंगा लेने की मुसीबत से भी ईरान बच जाएगा। ईरान अपने साथियों जैसे-लेबनान, सीरिया, यमन और ईराक से भी कहेगा कि हमला एक साथ हो ताकि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम इतनी ज्यादा मात्रा में आने वाले हवाई हमले को संभाल न सके। इससे अमेरिका और इजरायल को वापसी हमला करने या बचाव का कम समय मिलेगा। हिजबुल्लाह के ड्रोन 15 मिनट में हाइफा और 40 मिनट में तेल अवीव पहुंच सकते हैं।

कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर टिम वाल्ज को चुना

वॉशिंगटन(ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। कमला हैरिस ने अपने रनिंग मेट यानी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर टिम वाल्ज को चुना है। मगर कमला हैरिस की पसंद टिम वाल्ज का चीनी कनेक्शन सामने आया है। कमला हैरिस की पसंद टिम वाल्ज चीन के सो कॉल्ड यार निकल गए। चीन में लोग उन्हें प्यार से चाइनाज मैन कहते हैं। हालांकि, टिम वॉल्ज के इस चीन कनेक्शन को लेकर डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन ने घेरना शुरू कर दिया है।

दरअसल, डेमोक्रेटिक की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार टिम वाल्ज के चीन के साथ दशकों पुराने संबंध हैं। टिम वॉल्ज चीन में टीचर रह चुके हैं। वह 1989 और 1990 में चीन के दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत में स्थित कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे। टिम वाल्ज ने अक्सर चीन के लोगों के बारे में प्यार से बात की है। कहा जाता है कि चीन और चीनियों को लेकर उनका नजरिया जरा सॉफ्ट रहा है। वह कई बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। 90 के दशक में वह बीजिंग में यूएस अंबेसडर भी रह चुके हैं। वाल्ज के इसी चीनी कनेक्शन को लेकर अब रिपब्लिकन हमलावर हो गई है।

टिम वाल्ज नेब्रास्का के छोटे से शहर वेस्ट प्वाइंट में पले-बढ़े हैं। राजनीति में आने से पहले वह मिनेसोटा के मैनकैटो वेस्ट हाई स्कूल में सामाजिक अध्ययन के शिक्षक, फुटबॉल कोच और यूनियन के सदस्य रह चुके हैं। टिम वाल्ज ने आर्मी नेशनल गार्ड में 24 साल सेवा की और सेना में सबसे ऊंचे रैंक में से एक सार्जेंट मेजर की कमान संभाली। वह छह बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार वह 2006 में संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 2018 में 'वन मिनेसोटा' थीम पर गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ा और 11 से अधिक अंकों से जीत हासिल की। वाल्ज ने 2022 में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डॉ। स्कॉट जेन्सेन को मात दी थी।

ट्रम्प प्रशासन में जर्मनी में राजदूत और कार्यकारी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक रहे रिचर्ड ग्रेनेल ने एक्स पर कहा, 'कमला के उपराष्ट्रपति के रूप में टिम वाल्ज के चयन से कम्युनिस्ट चीन बहुत खुश है। हालांकि, कमला हैरिस और टिम वाल्ज की टीम ने इस तरह की आलोचना को खारिज किया है। टीम कमला के प्रवक्ता जेम्स सिंगर ने कहा, 'रिपब्लिकन बुनियादी तथ्यों को तोड़-मरोड़ रहे हैं। वाल्ज लंबे समय से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खड़े रहे हैं और मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए लड़े हैं। उन्होंने हमेशा अमेरिकी नौकरियों और विनिर्माण को सबसे पहले रखा है।

रेलवे पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 11 ठिकानों पर की छापेमारी

50-60 अभ्यर्थियों को पहले दिया गया था पेपर

लखनऊ (ईएमएस)। प्रयागराज रेलवे भर्ती बोर्ड की डीजीसीई (जनरल डिपार्टमेंट कंपटीटिव एग्जाम) का पेपर लीक मामले में सीबीआई ने राजस्थान और यूपी में 11 ठिकानों पर छापा मारा है। सीबीआई की टीमों ने प्रयागराज, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, चित्रकूट व राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर में क साथ छापा मारकर दस्तावेज बरामद किए हैं।

रेलवे बोर्ड के उपनिदेशक विजिलेंस अनिल कुमार मीना की शिकायत पर सीबीआई लखनऊ, की एंटी करप्शन ब्रांच ने परीक्षा देने वाले और पेपर लीक कराने के बदले पैसा लेने वाले 11 रेलकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, परीक्षा कराने वाली एजेंसी अपटेक लि. को भी आरोपी बनाया गया है। रेलवे ने शिकायत में अपनी विजिलेंस जांच रिपोर्ट का हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 6 अगस्त 2021 को आयोजित डीजीसीई परीक्षा का पेपर लीक करके 50-60 अभ्यर्थियों को पढ़वाया गया था।

सीबीआई केस में नामजद आरोपी

ट्रैक मेंटेनर राजस्थान के भरतपुर के भूप सिंह, वेगराज, महावीर सिंह व प्रीतम सिंह, अलवर का जितेंद्र कुमार मीना, सवाई माधोपुर का प्रमोद कुमार मीना, टोंक का हंसराज मीना, अलीगढ़ का धर्म देव, करौली का प्रशांत कुमार मीना, जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य अभियंता कार्यालय का कार्यालय अधीक्षक मान सिंह के अलावा नोएडा का पार्सल पोर्टर मोहित भाटी शामिल है।

म्युचुअल फंड और शेयर बाजार के नए निवेशक सावधान रहें

नई दिल्ली (ईएमएस)। पिछले कई वर्षो से शेयर बाजार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है। म्युचुअल फंड के माध्यम से बड़ी तेजी के साथ शेयर बाजार में निवेश बढ़ा है। छोटे निवेशकों ने 16 करोड़ डीमैट खाता खोल रखे हैं। इसमें छोटे-छोटे निवेशक निवेश कर रहे हैं।

म्युचुअल फंड के माध्यम से हर महीने शेयर बाजार में 21000 करोड रुपए निवेश किया जा रहे हैं। शेयर बाजार में म्युचुअल फंड की भागीदारी बढ़ने से बाजार तेजी के साथ भाग रहा था। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से मुनाफा वसूली करके बाहर निकल रहे हैं। उससे ज्यादा निवेश, छोटे निवेशक कर रहे हैं।

जिस तरह से विश्व के शेयर बाजारों में आर्थिक मंदी का असर दिखने लगा है। भारत के शेयर बाजार भी तेजी के साथ गिरे हैं। आने वाले दिनों में मुनाफा वसूली और बाजार से निकलने की कोशिश में बाजार में तेजी के साथ गिरावट आएगी। नए निवेशकों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। म्युचुअल फंड तथा छोटे निवेशकों द्वारा,जो शेयर बाजार में सीधे निवेश करते हैं। उनके लिए यह समय बहुत सोच समझकर निवेश करने का है। नए निवेशकों ने अभी बाजार का केवल एक ही चेहरा तेजी का देखा है। शेयर बाजार जब गोता लगाता है। तो किस स्तर तक नीचे जाता है। इसका एहसास छोटे निवेशकों को नहीं है। अतः छोटे और नए निवेशक शेयर बाजार में सावधानी के साथ निवेश करें।

एक साल बाद खुले भगवान नाग चंद्रेश्वर के पट, भक्तों की लगी भीड़

उज्जैन,(ईएमएस)। सावन के महीने में नागपंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा के मुताबिक रात 12 बजे खोले गए। मंदिर में रात से बराबर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का यह सिलसिला 24 घंटे तक चलता रहेगा। नागचंद्रेश्वर के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।

बाबा महाकाल के दरबार में नाग पंचमी पर्व पर नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 12 साल में एक बार रात को नागचंद्रेश्वर के पट पूजन के बाद खोले गए। भगवान नागचंद्रेश्वर का जल दूध दही घी से पंचामृत अभिषेक किया गया जिसके बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन करना शुरू किए। शाम को पंडित पुजारियों द्वारा पूजन पाठ किया जाएगा देर रात 12 बजे मंदिर का पट फिर से बंद कर दिया जाएगा जो एक साल बाद खुलेगा।

महाकालेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यहां महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजे शिव-पार्वती की दुर्लब मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव-पार्वती प्रसन्न होते हैं साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। नागपंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है इसलिए श्रद्धालु यहां नाग की प्रतिमा पर दूध चढाते हैं। उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मन्दिर में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी के परमार काल की हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा में शेषनाग की सैय्या पर भगवान शिव और पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिक भी विराजित है। बताया जाता है की यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। भगवान महाकाल के दरबार में स्थित नागचंद्रेश्वर का मंदिर साल में केवल एक बार ही खुलता है।

वक्फ बोर्ड में पहले से ही हैं दो महिलाएं फिर संशोधन की बात क्यों?

नई दिल्ली,(ईएमएस)। सदन में वक्फ बिल लोकसभा में पेश हुआ और इस पर जोरदार बहस भी हुई। इसके बाद जो हुआ उसका सार गालिब के इस शेर में है-थी ख़बर गर्म कि ग़ालिब के उड़ेंगे पुर्ज़े, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। ऐसा माना जा रहा था वक्फ बिल का विपक्ष विरोध करेगा इसके पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। सपा सांसद ने तो खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि सरकार ने इसमें बदलाव किया तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन सब के बीच मोदी सरकार ने इस बिल को जेपीसी कमेटी के पास भेज दिया। अब जेपीसी में सभी पक्ष अपनी राय रख सकेंगे।

सरकार के इस वक्फ बिल में 40 बदलाव प्रस्तावित हैं। मसलन महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही जा रही है। सेक्शन 9 और 14 में बदलाव करके वक्फ परिषद में दो महिलाओं को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। ऐसा कहा जा रहा है इसमें एक भी महिला नहीं होती थी। इस बाबत दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य और दिल्ली बॉर काउंसिल के को-चेयरमैन एडवोकेट हमील अख्तर ने बताया कि वक्फ बोर्ड में पहले से ही दो महिला सदस्य रहती हैं। उन्होंने भंग होने पहले के वक्फ सदस्यों का उदाहरण देते हुए बताया कि दिल्ली में सात सदस्यी ईकाई में दो महिला सदस्य हैं नईम फातिमा काज़मी और रजिया सुल्ताना थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लेकर भी उन्होंने सबिहा अहमद, तबस्सुम खान के रूप में दो महिला सदस्यों के नाम का जिक्र भी किया।

मोदी सरकार ने तीसरे टर्म के अपने पहले बिल को सीधे सदन में पास कराने के बजाय चर्चा और मशविरे के लिए संसद की कमिटी के पास भेजने की विपक्ष की मांग मान ली। इसे लोकसभा की स्थायी समिति के पास भेजने की बजाय संसद की जेपीसी के सामने भेजने पर सहमति बनी। इसके पीछे कुछ वजह है। लोकसभा में अभी स्थायी समिति नहीं बनी है। कई बार स्थायी समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल के सीनियर नेता होते हैं। जेपीसी अध्यक्ष ज्यादातर सत्ता में काबिज दल का होता है, हालांकि उसमें सभी दलों की भागीदारी होती है। लेकिन सत्तारूढ़ दल के सदस्य ज्यादा होंगे।

ईडी, सीबीआई और विरोधियों के चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे लालू के लाल तेजस्वी

-रही सही कसर प्रशांत किशारे ने पूरी कर दी

पटना (ईएमएस)। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डेप्युटी सीएम तेजस्वी यादव चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दाखिल सीबीआई की पूरक चार्जशीट तेजस्वी के गले की फांस बन गई है। तेजस्वी 17 अगस्त से बिहार के जिलों के दौरे पर निकलने की घोषणा कर चुके हैं। इसकी तैयारियां भी आरजेडी कर रही हैं। दरअसल आरजेडी की चिंता लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बढ़ गई है। मजबूत गठबंधन और आरजेडी के बड़े जनाधार के बावजूद 23 में सिर्फ चार सीटों पर ही जीत से चिंता स्वाभाविक है। आरजेडी की चिंता जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बढ़ा दी है। दरअसल पीके के निशाने पर सबसे अधिक लालू के लाल तेजस्वी ही दिख रहे हैं। उनकी रणनीति जो अब तक सामने आई है, उससे आरजेडी के आधार वोट बैंक में बिखराव के खतरे बढ़ गए हैं। जेडीयू और भाजपा आरजेडी के पुराने दुश्मन ही रहे हैं।

जमीन के बदले नौकरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जो पूरक चार्जशीट दाखिल की है, उसमें तेजस्वी का भी नाम है। ईडी ने उन पर मनी लांड्रिंग का मामला कायम किया है। चार्जशीट में तेजस्वी यादव के अलावा उनके पिता लालू प्रसाद यादव सहित 11 लोगों आरोपी बनाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। तेजस्वी अपने परिवार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की रूटीन कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को मामले में गिरफ्तारी का भय भी सता रहा है। इस मामले की दो केंद्रीय एजेंसियां- सीबीआई और ईडी जांच कर रही है।

वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में जिस तरह का भूचाल ला दिया है, उसकी आहट अब स्पष्ट सभी राजनीतिक दल महसूस कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक चिंता आरजेडी कैंप में ही है। इसके पीछे वजह पीके के निशाने पर हमेशा ही तेजस्वी ही रहते हैं। तेजस्वी की योग्यता और उनके परिवार के शासन काल की नाकामियों को लेकर प्रशांत किशोर लोगों को न सिर्फ जागरूक करते रहे हैं, बल्कि आरजेडी के आधार वोट में सेंध लगाने का पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। आरजेडी मुसलमानों को अपना आधार वोट मानता है। आरजेडी के एम-वाई समीकरण का एक घटक मुसलमान ही हैं। प्रशांत ने मुसलमानों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 75 सीटें देने का ऐलान कर आरजेडी नेताओं की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर से जन सुराज से जिस तरह आरजेडी के नेता जुड़ने लगे हैं, वह भी पार्टी के लिए चिंता का विषय है।

एनडीए में शामिल भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हम (से) और आरएलएम के नेता पहले से तेजस्वी के विरोध में हैं। भाजपा क नेता यहां तक कहने लगे हैं कि सीबीआई और ईडी से तेजस्वी का बचना मुश्किल है। उनका जेल जाना तय है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह के हमले तेजस्वी और उनके परिवार के खिलाफ किए, इससे साफ हैं कि जेडीयू तेजस्वी के प्रति किसी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। तेजस्वी और उनके पिता लालू को अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार विपक्षी इंडिया ब्लॉक के साथ आ जाएंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति में यह संभव नहीं दिखता, क्योंकि भाजपा ने अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ने का ऐलान कर उनके मन की मुराद पूरी कर दी है। संसद में भी जेडीयू और भाजपा की युगलबंदी देखकर आरजेडी को जरूर निराशा हुई होगी।

पिता-पुत्र ने सगी बेटी-बहन के साथ किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर भांडा फूटा

साबरकांठा (ईएमएस) पिता-पुत्री और बहन-भाई के पवित्र रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना साबरकांठा से सामने आई है। पिता ने अपनी सगी बेटी और भाई ने सगी बहन के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के इस मामले में अन्य शख्स जो पीड़ित की लड़की के पिता को दोस्त है, वह भी शामिल है। पिता-पुत्र के पाप का भांडा उस वक्त फूट गया, जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। पीड़ित लड़की की माता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। पवित्र रिश्तों को तार तार कर देनेवाली यह घटना साबरकांठा जिले के तलोद की है। जहां एक प्रवासी परिवार की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्मी और कोई नहीं पीड़ित के सगे पिता और सगे भाई समेत उसके पिता के दोस्त ने किया। तीनों आरोपियों ने नाबालिग लड़की को अलग अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों के पाप का भांडा तब फूट गया, जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। पीड़िता की माता को जब पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कल्पना तक नहीं की होगी उसका बेटा और पति अपनी सगी बहन-बेटी के साथ दुष्कर्म कर सकता है। महिला ने तुरंत अपने पति, बेटे और पति के दोस्त के खिलाफ तलोद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। तलोद पुलिस ने दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। घटना सामने आने के बाद लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। लोगों की मांग है कि ऐसे दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

आदिवासी खिलाड़ियों में जोश भरने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत

गांधीनगर 09 अगस्त

राज्य सरकार नई पहलों और सहायताओं के जरिए आदिवासी खिलाड़ियों में जोश भरने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 में अरवल्ली, बनासकांठा, भरूच, दाहोद, डांग, नर्मदा, नवसारी, पंचमहाल, साबरकांठा, सूरत, तापी और वलसाड के 15 जिला स्तरीय खेल स्कूलों के लिए 13,91,70,615 रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। इन स्कूलों में 1000 से अधिक आदिवासी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, गत 10 वर्षों में 15 आदिवासी खिलाड़ियों को खेल प्रतिभा पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। गुजरात सरकार ने राज्य के होनहार खिलाड़ियों में निहित क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यकता-आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराकर 'चैंपियन' तैयार करने के लिए 'शक्तिदूत योजना' लागू की है। इस योजना के अंतर्गत सरिता गायकवाड़ को वर्ष 2017 से 2024 के दौरान 12 लाख रुपए की सहायता दी गई है, जबकि मुरली गावित को इसी अवधि के दौरान 55,92,806 रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

राज्य सरकार 'स्वामी विवेकानंद गैर-निवासी प्रतिभा संवर्धन केंद्र' के अंतर्गत प्रति खिलाड़ी सालाना लगभग 65 हजार रुपए का खर्च करती है। इस योजना के अंतर्गत 336 आदिवासी खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 7 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीते हैं। वहीं, राज्य सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद प्रतिभा संवर्धन केंद्र-आवासीय अकादमी के तहत प्रति खिलाड़ी सालाना लगभग 3 लाख रुपए का खर्च किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र के 444 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 350 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 41 सहित कुल 391 पदक अपने नाम किए हैं। खेल क्षेत्र में राज्य सरकार की एक और पहल- 'इनस्कूल योजना' के अंतर्गत 14 आदिवासी जिलों के 79 स्कूलों में विद्यार्थी विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें स्कूल के दौरान 37,000 और आफ्टर सेशन में 4000 से अधिक खिलाड़ी शामिल हैं। इतना ही नहीं, गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित 9 'खेलो इंडिया जिला केंद्र' में कुल 292 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मेगा स्पोर्टिंग इवेंट 'खेल महाकुंभ' के अंतर्गत 2023 में आयोजित खेल महाकुंभ 2.0 में 16,86,331 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। विजेताओं को गुजरात सरकार की ओर से करोड़ों रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के आयोजन में भी राज्य सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2023-24 की 67वीं एसजीएफआई की अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 प्रतिस्पर्धाओं में 24 लड़कियों और 9 लड़कों सहित गुजरात के कुल 33 खिलाड़ियों ने खो-खो, हैंडबॉल, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, सॉफ्ट टेनिस, वॉलीबॉल और कुश्ती जैसे खेलों में पदक जीते हैं।

कांग्रेस की 'न्याय यात्रा' को बड़ा झटका, राजकोट के पीड़ित परिवारों ने शामिल होने से किया इंकार

अहमदाबादः गुजरात में कांग्रेस कीन्याय यात्रा को शुरुआत के साथ ही बड़ा झटका लगा है। राजकोट टीआरपी गेमजोन अग्निकांड के पीड़ितों ने कांग्रेसकी न्याय यात्रा में जुड़ने और शामिल होने से मना कर दिया है। गुजरात कांग्रेस ने राज्य में पिछले महीनों में हुए बड़े हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मोरबी से यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस की यात्रा 9 अगस्त को मोरबी ब्रिज हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुई, लेकिन उधर राजकोट में कुछ पीड़ित परिवारों ने न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया।

अपने परिवार के सदस्यों को गंवाने वाले इन पीड़ितों का कहना है कि न्याय यात्रा से कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। जो भी न्याय मिलेगा वह कोर्ट से मिलेगा। तो वहीं दूसरी कुछ पीड़ितों ने साकार की तरफ से की जा रही जांच पर संतोष व्यक्त किया है। इस कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

गुजरात में कांग्रेस को न्याय यात्रा की शुरुआत के साथ ही बड़ा झटका लगा है। मोरबी से यात्रा के शुरू होने के साथ ही राजकोट के पीड़ित परिवारों ने इस यात्रा का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। टीआरपी गेमजोन अग्निकांड के पीड़ितों ने कहा कि न्याय यात्रा से कुछ नहीं होगा।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात दौरे में राजकोट, वडोदरा और सूरत समेत मोरबी के पीड़ितों से मुलाकात की थी। राजकोट के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पहली मासिक बरसी पर कांग्रेस ने राजकोट का बंद भी रखा था। जो सफल हुआ था। राजकोट के कुछ पीड़ितों द्वारा न्याय यात्रा में शामिल होने से इंकार करने पर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति (जीपीसीसी) के प्रवक्ता हेमांग रावल ने कहा कि मोरबी से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा को लोगों का समर्थन मिला है। इसी को देखते हुए बीजेपी घबरा गई है।

टैंकर और ईको कार के बीच भीषण हादसे में पांच लोगों की मौत

पंचमहल (ईएमएस) जिले के गोल्लाव के पास एक ईको कार और टैंकर के बीच दर्दनाक हादसा होने की खबर है। इस हादसे में इको में सवार 7 में से 5 लोगों की मौत हो गई है। जबकि गंभीर रूप से घायल दो लोगों को उपचार के लिए वडोदरा भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक पंचमहल जिले के गोधरा में गोल्लाव के निकट टैंकर और ईको कार के जबर्दस्त भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टैंकर की टक्कर से ईको कार के परखच्चे उड़ गए और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। टैंकर की टक्कर से ईको कार की हालत यह हो गई थी कि उसमें फंसे लोगों को कार के पतरे काट कर बाहर निकालना पड़ा। गंभीर रूप से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जहां एक और शख्स की मौत हो गई। अन्य दो में से एक व्यक्तिकी हालत बेहद गंभीर है, उसे आगे के इलाज के लिए वडोदरा भेजा गया है। प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि ईको में सवार लोग छोटाउदेपुर जिले के रहनेवाले थे। घटना के वक्त कार में 7 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है।

राजकोट में बीजेपी सांसद के कार्यालय में नहीं है फायर एनओसी, अग्निशमन विभाग ने जारी किया नोटिस

राजकोट,9 अगस्त

आग लगने की घटना के बाद अग्नि सुरक्षा सुविधाओं की कमी के कारण कईस्कूलों, दुकानों, कॉम्प्लेक्स समेत कई जगहों को सील कर दिया गया. हालांकि, इस बीच पिछले महीने राज्यसभा सांसद राम मोकारिया की कंपनी मारुति कूरियर के कॉरपोरेट हाउस में आग लगने की घटना हुई थी. जांच के बाद पता चला कि कार्यालय में कोई फायर एनओसी नहीहैऔर नगर पालिका के अग्निशमन विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया था।

राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में आग लगने की घटना के बाद, राजकोट नगर निगम ने फायर एनओसी जारी की। मामले में नोटिस जारी कर भवनों व गोदामों को सील करने की कार्रवाई की गई। राजकोट में याग्निक रोड पर मारुति कूरियर के कॉर्पोरेट हाउस को भी नोटिस जारी किया गया है। यह कार्यालय राज्यसभा सांसद राम मोकारिया का है और वह खुद भी इसी कार्यालय में बैठते हैं, जहां फायर एनओसी नहीं होने पर नगर पालिका के अग्निशमन विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है.

प्राप्त विवरण के अनुसार नियमानुसार व्यावसायिक परिसर की ऊंचाई 9 मीटर से अधिक होने पर फायर सिस्टम लगाना अनिवार्य है। लेकिन मारुति कूरियर के ऑफिस में फायर सिस्टम नहीं होने के कारण अग्निशमन विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है. इस नोटिस के मिलने के एक सप्ताह के अंदर फायर सिस्टम के संबंध में कार्रवाई नहीं करने पर बिल्डिंग को सील करने का प्रावधान है.

हालांकि, जुलाई महीने के दौरान याग्निक रोड पर मारुति कूरियर के कार्यालय में एक पार्सल के अंदर आग लग गई। वहां मौजूद कर्मियों ने अग्निशमन यंत्रों से आग बुझा दी, लेकिन आग की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी भी भेजी गई। बाद में जांच में पता चला कि फायर एनओसी नहीं थी। इसलिए अग्निशमन विभाग की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया है, जिससे पता चलता है कि उनके पास फायर एनओसी नहीं है।

गुजरात स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, डेंगू पर नियंत्रण के लिए चलाया गया अभियान

9 अगस्त 2024

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस वर्ष जुलाई से अक्टूबर माह के दौरान पूरे राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न माध्यमों से डेंगू रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।

जैसा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, डेंगू एक बीमारी है जो आर्बोवायरस के कारण होती है और एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलती है। यह मच्छर एक चम्मच भर पानी में भी अंडे देता है और दिन भर काटता है। आमतौर पर जुलाई से अक्टूबर महीने के दौरान डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होती है।

डेंगू रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता पैदा करने और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी में शामिल होने के लिए हर साल जुलाई महीने को 'डेंगू विरोधी माह' के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम समुदाय से जुड़ें, डेंगू पर नियंत्रण रखें तय की गई है। जिसके तहत इस वर्ष डेंगू रोग और उससे होने वाली मृत्यु को रोकने में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए पूरे प्रदेश में यह उत्सव एक अभियान के रूप में चलाया गया है।

नागरिकों को डेंगू के मच्छरों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की सूची में आगे कहा गया है कि डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों के काटने से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें और शरीर के खुले हिस्सों पर मच्छर रोधी क्रीम का प्रयोग करें। डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए मच्छरदानी, सभी जल भंडारण कंटेनरों को वायुरोधी बनाएं, ढक्कन बंद रखें, हर सप्ताह सभी फूलदानों, कुंडों, पक्षियों के घरों और जल भंडारण कंटेनरों को खाली करें, रगड़ें, साफ करें, सुखाएं और उपयोग करें, बेकार खाली कंटेनरों, स्क्रैप का निपटान करें। घर में, छत पर और घर के आसपास टायर, नारियल का खोल आदि।

डेंगू और चिकनगुनिया के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए डॉक्टर के मार्गदर्शन के बिना दवा न लें, तेज बुखार, आंखों की पुतलियों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और शरीर पर दाने या खसरा जैसे चकत्ते होने पर नजदीकी सरकारी अस्पताल और डेंगू के लिए संपर्क करना चाहिए। चिकनगुनिया के मरीज को इलाज के लिए एस्पिरिन लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सूची में आगे कहा गया है कि दवा का इस्तेमाल न करें।

गुजरात की जीवनरेखा सरदार सरोवर योजना का जलस्तर पहुंचा 128 मीटर पर

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात की जीवनरेखा माने जाते राज्य के सबसे बड़े बांध सरदार सरोवर नर्मदा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण मध्य प्रदेश के अधिकांश बांधों से पानी छोड़ना शुरू हो गया है, जिससे नर्मदा बांध का जल स्तर में इजाफा हो रहा है। फिलहाल नर्मदा बांध का जलस्तर 128 मीटर तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक जलस्तर अभी भी और बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के बांधों से पानी छोड़े जाने से जलस्तर बढ़ेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर और इंदिरासागर बांध से पानी छोड़ा गया है, ओंकारेश्वर के 18 गेट, इंदिरासागर बांध के 12 गेट खोले गए है। नर्मदा बांध में अपस्ट्रीम से 1.60 लाख क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। नर्मदा बांध का अधिकतम स्तर 138.68 मीटर है। दूसरी ओर जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में सीजन की कुल औसत से 67 फीसदी से ज्यादा बारिश हो चुकी है कच्छ क्षेत्र में सबसे ज्यादा 86 प्रतिशत से अधिक, दक्षिण गुजरात में 81 प्रतिशत से अधिक और सौराष्ट्र क्षेत्र में 77 प्रतिशत से अधिक बारिश हुई। जबकि उत्तरी गुजरात में 50 फीसदी और पूर्वी-मध्य गुजरात में सीजन की कुल औसत बारिश से 84 फीसदी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। राज्य में भारी बारिश के परिणामस्वरूप, 47 जलाशय पूरी तरह से भर गए हैं, जबकि 10 जलाशयों को 90 से 100 प्रतिशत भरने के साथ हाई अलर्ट पर घोषित किया

20 कोच के साथ देश की पहली वंदे भारत ट्रेन 130 किमी की रफ्तार से दौड़ी

अहमदाबाद (ईएमएस) अहमदाबाद-मुंबई के बीच आज 20 कोच के साथ देश की पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल लिया गया। ट्रायल सफल रहा तो इसमें अतिरिक्त कोच जोड़े जा सकते है। बता दें कि फिलहाल अहमदाबाद-मुंबई के बीच वंदे भारत ट्रेन 16 कोच के साथ चल रही है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए वंदे भारत ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़ने की कवायद चल रही है। इसी के अंतर्गत आज वंदे भारत ट्रेन में 20 कोच जोड़कर 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रायल लिया गया। बताया जाता है कि अगर ट्रायल सफल रहा तो इसमें और भी कोच बढ़ाए जा सकते है। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ट्रायल की शुरुआत हुई। 20 कोच के साथ शुरू होनेवाली नई वंदे भारत ट्रेन करीब साढ़े चार घंटे में अहमदाबाद से मुंबई पहुंचाएगी। देश में पहली बार वंदे भारत ट्रेन 20 कोच के साथ चलेगी। ट्रेन की सुरक्षा के लिए 24 घंटे आरपीएफ के जवान तैनात किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में साबरकांठा जिले के खेड़ब्रह्मा में राज्य स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया

गांधीनगर 09 अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को साबरकांठा जिले की खेड़ब्रह्मा तहसील के नवी मेत्राल गांव के आर्डेकता इंस्टीटयूट में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मूल निवासी के रूप में पहचाने जाने वाले आदिवासी सदियों से आध्यात्मिक रूप से प्रकृति के साथ-साथ बिरसा मुंडा की भी पूजा करते आए हैं। आदिवासी समाज के भव्य इतिहास और गौरवशाली संस्कृति, परम्परा तथा अस्मिता को बनाए रखने के एक भाग के रूप में हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंबाजी से लेकर उमरगाम तक बसे आदिवासी बंधुओं को पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रयासरत रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात को आदिवासी विकास के एक विशिष्ट मॉडल के तौर पर स्थापित किया है। अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। मानगढ़ में गोविंद गुरु हो या पाल दढवाव में मोतीलाल तेजावत, स्वतंत्रता संग्राम के समय आदिवासियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारत को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली हैं। प्रधानमंत्री ने आदिम समूहों के 30 हजार परिवारों के 1.50 लाख लोगों के विकास के लिए 'पीएम-जनमन' अभियान शुरू किया है।

पटेल ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास और सड़क जैसी मनुष्य की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रही है। वन बंधु कल्याण योजना, वन अधिकार अधिनियम, समरस छात्रालय, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना और दूध संजीवनी योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में आदिवासी विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। वनबंधु कल्याण फेज-2 के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान और 30 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, नल से जल, जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र-जीआईडीसी की स्थापना से नए रोजगार अवसर उपलब्ध होने के कारण जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार आया है।

उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम' अभियान के तहत देश के 63 हजार गांवों के पांच करोड़ आदिवासियों के सौ फीसदी विकास का संकल्प लिया गया है। आदिम समूहों को सामाजिक और आर्थिक विकास के जरिए मुख्यधारा में शामिल करने के लिए पीएम-जनमन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के बच्चे शहरी इलाकों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए शैक्षणिक संस्थान बनाए गए हैं। आदिवासी बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और आदिवासी कोटे की सीटों को पूर्ण रूप से भरने के लिए 360 डिग्री परिवर्तन लाया गया है।

इस अवसर पर आदिजाति विकास और शिक्षा मंत्री श्री कुबेरभाई डिंडोर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी विकास को गति मिली है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए कोचिंग की सुविधा मिलने से आज आदिवासी विद्यार्थी इन कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं।

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के करकमलों से समग्र राज्य में 411.37 करोड़ रुपए के 2240 कार्यों का शिलान्यास और 602.78 करोड़ रुपए के 2053 कार्यों के लोकार्पण सहित कुल 1014.14 करोड़ रुपए के 4293 कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है।

इनमें से साबरकांठा जिले में मुख्यमंत्री ने 3762.88 लाख रुपए के 216 कार्यों का शिलान्यास तथा 2091.37 लाख रुपए के 197 कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने 7618 लाभार्थियों को विभिन्न विभागों की व्यक्तिगत योजना के 4682.00 लाख रुपए के लाभ प्रदान किए।

विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समुदाय के विद्यार्थियों ने परम्परागत सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के एक बालक द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथ का विमोचन भी किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती भारतीबेन पटेल, हिम्मतनगर के विधायक श्री वी.डी. झाला, इडर के विधायक श्री रमणलाल वोरा, प्रांतिज के विधायक श्री गजेन्द्रसिंह परमार, अपर मुख्य सचिव (आदिजाति विकास) श्री जे.पी. गुप्ता, साबरकांठा कलेक्टर श्री नैमेश दवे, रेंज आईजी श्री मनीष सिंह, जिला विकास अधिकारी श्री हर्षद वोरा, जिला पुलिस अधीक्षक श्री विजय पटेल, परियोजना प्रबंधक श्री विशाल सक्सेना सहित जिले के अधिकारी उपस्थित रहे।

मैडम अमेरिका में रहती हैं और सरकारी स्कूल में चल रही शिक्षिका की नौकरी,बनासकांठा में हैरान करने वाला मामला

अहमदाबादः गुजरात में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह मामला बनासकांठा जिले की अंबाजी के पास के एक सरकारी स्कूल से जुड़ा हुआ है। यहां पर एक शिक्षिक अमेरिका में रहती हैं लेकिन वह स्कूल की शिक्षिका भी हैं। मजेदार बात यह है किवह सैलरी भी ले रही हैं। सवालखड़ा हो रहा है क्या स्थानीय अधिकारियों की बिना मिलीभगत के यह संभव है।जांच में सामने आया है कि उनकी जब इच्छा होती है तो वह दिवालीपर10महीने बाद आ जाती हैं औरफिर21दिन की छुट्टियां भी लेतीहैं। अमेरिका में रहकर बनासकांठा जिले के अंबाजी स्थित स्कूल पढ़ा रही शिक्षिका का फर्जीवाड़ा सामने आने पर सरकार में हड़कंप की स्थिति है। यह भी सामने आया है कि शिक्षिका दो महीने भारत में और 10 महीने यूएस में रहती हैं।

गुजरात में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। प्राइमरी स्कूल में तैनात एक स्कूल शिक्षिक सालों से अमेरिका में रह रही हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इसके बाद भी शिक्षिका की गुजरात में नौकरी चल रही है। मामले के खुलासे के बाद अब सरकार के स्तर हड़कंप की स्थिति है।

यह सनसनीखेज मामला बनासकांठा जिले की दांता तहसील में अंबाजी के पास पंचा प्राथमिक विद्यालय का है। स्कूल की शिक्षिक भावनाबेन पटेल पिछले आठ सालों से अमेरिका में रह रही हैं। वे कभी-कभी ही स्कूल में आती है। नवगुजरात समय की रिपोर्ट के अनुसार भावना पटेल के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड भी है, फिर भी भारत के इस सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में उनका नाम दर्ज है। स्कूल बोर्ड पर नाम अंकित है। आरोप है कि इस संबंध में कई बार ज्ञापन देने के बाद भी अधिकारियों की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्कूल के प्रभारी शिक्षक का कहना है कि वह प्रभारी यह शिक्षक साल में एक बार दिवाली के समय आती हैं। दिवाली की छुट्टियों का वेतन भी निर्धारित करती है।

कांग्रेस की न्याय यात्रा का मकसद राज्य में कानून-व्यवस्था बिगाड़ना है : नितिन पटेल

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने राज्य में आज से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा पर कड़े प्रहार किए। नितिन पटेल ने कहा कि फिलहाल राज्य में कानून-व्यवस्था बेहतर है और उसे बिगाड़ने के लिए कांग्रेस ने न्याय यात्रा का आयोजन किया है। बता दें कि गुजरात कांग्रेस ने मोरबी ब्रिज हादसा, राजकोट गेम जोन अग्निकांड, सूरत तक्षशिला अग्निकांड, वडोदरा हरणी बोट कांड समेत विभिन्न दुर्घटनाओं के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से 9 से 23 अगस्त के दौरान राज्य में न्याय यात्रा का आयोजन किया है। पिछले साल मोरबी में हुई ब्रिज दुर्घटनास्थल से कांग्रेस की न्याय यात्रा आजसे शुरूहो गई है। इस न्याय यात्रा को लेकर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि वर्तमान में राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर बनी हुई है। कांग्रेस पूरे राज्य की शांति भंग करने के लिए न्याय यात्रा निकाल रही है। मेरे विचारसे अब रैली आयोजित करना अप्रासंगिक है। कांग्रेस की रैली का उद्देश्यअप्रासंगिक है। जिस मुद्दे पर रैली हो रही है उस पर सरकार और हाईकोर्ट ने कार्रवाईकी है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी लगातारमॉनिटरिंग कर रहे है। उन्होंने कहाकिपुरानी घटनाओं को लेकर कांग्रेस का न्याययात्रा काआयोजन ठीक नहीं है। कांग्रेस को अगर राजनीति करनी है तो ऐसे कई प्रसंग आएंगे, जिसे लेकर वह जनता के बीचजा सकती है। नितिन पटेल ने कहा कि पीड़ित परिवार से सहानुभूति हासिल करने के लिए कांग्रेस न्याय यात्रा कर रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्षभरत बोघरा ने कहा कि कांग्रेसने राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए न्याय यात्रा का आयोजन किया है। लेकिन पिछले 28 साल से भाजपा गुजरात की जनता के आशीर्वाद से राज्य में शासन कर रही है। कांग्रेस पर कड़े प्रहार करते हुए भरत बोघरा ने कहा कि कांग्रेस शासन में तो गांव भी गुंडों के नाम से पहचाने जाते थे। पीड़ितों के कंधे पर हाथ रखकर कांग्रेस अपनी राजनीति चमकान निकली है। साथ ही भरत बोघरा ने कांग्रेस पर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का भी आरोप लगाया।

अमरेली में 'सांडों की लड़ाई' किसने रखी थी... गुजरात हाईकोर्ट का तंज

अहमदाबादः गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर गंभीर टिप्पणी करते हुए तंज कसा है। आवारा पशुओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अमरेली के धारी की घटना का जिक्र करके कोर्ट ने पूछा कि वहां पर 'सांडों की लड़ाई' का आयोजन किसने किया था? कोर्ट ने कहा अब हमें व्हाट्सएप पर भी वीडियो मिलते हैं।धारी के मुख्य द्वार हुई घटना में एक दोपहिया वाहन चालक को सांडों ने कुचल दिया, जबकि एक अन्य मोटरसाइकिल चालक भी बाल-बाल बच गया था। वह अपनी जान बचाकर भाग गया। तो वहीं सड़क से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों में भी सांडों की लड़ाई के कारण भगदड़ मच गई थी। सांडों के हमले में तुषार पटेल नामक डॉक्टर घायल हो गए थे।

गुजरात हाईकोर्ट में निलय पटेल नामक पेटीशनर ने आवारा मवेशियों से हो रहे हादसे पर याचिका 2021 में लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कई निर्देश दिए थे जिस पर राज्य सरकार की ओर से कार्यवाही नही होने के बाद अमित पांचाल नामक याचिकाकर्ता ने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अमरेली के धारी के बुल फाइट का जिक्र करते हुए तंज कसा और पूछा की अमरेली के धारी में इस बुल फाइट का आयोजन किसने किया था ? धारी की इस घटना में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसका संज्ञान तक गुजरात हाईकोर्ट ने लेते हुए कहा की याचिकर्ता तक ने कई तस्वीरें गांधीनगर के अडालज से कलोल रोड तक की कोर्ट को दी हैं।

वडोदरा में रिटर्निंग दीवार गिरी, मुख्य जल लाइन टूटीः पानी की बर्बादी

वड़ोदरा 9 अगस्त

वड़ोदरा शहर में कल शाम हुई भारी बारिश के कारण कारेलीबाग के कसम आला कब्रिस्तान के पास चतुरभाईचाली में रिटर्निंग दीवार ढह गई और नीचे से गुजरने वाली मुख्य पेयजल लाइन भी ढह गई, जिससे हजारों लीटर पीने का पानी बर्बाद हो गया। इस टूटी लाइन से नागरवाड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या हो जाएगी। गौरतलब है कि छह साल पहले भी इसी दीवार के गिरने से एक महिला समेतकुछघोड़ों की मौत हो गयी थी. हाल ही में दीवार गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गौरतलब है कि कल शाम शहर में कुछ ही घंटों में तीन बार मूसलाधार बारिश हुई.

संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड ने नए CEO और COO की नियुक्ति की घोषणा की

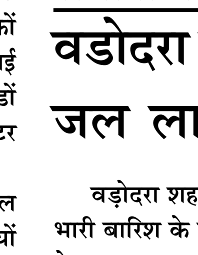

अहमदाबाद : माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री कंपनी, संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड (`SMIORE' या 'द कंपनी'), चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के रूप में कृष्णेंदु सान्याल और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) के रूप में मंजूनाथ प्रभु की नियुक्ति की घोषणा करते हुए प्रसन्न है। इन लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स का उद्देश्य कंपनी के मैनेजमेंट बैंडविड्थ को बढ़ाना और मेटल और माइनिंग इंडस्ट्री में इंटीग्रेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाना है।

नवनियुक्त र्ध्ं कृष्णेंदु सान्याल के पास स्ट्रैटजिक, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल लीडरशिप में 32 साल का अनुभव है। उन्होंने भारत और श्रीलंका में टाटा स्टील, थाईलैंड में सियाम इंडस्ट्रियल वायर कंपनी और दक्षिण अफ्रीका में सेडीबेंग आयरन ओर जैसी कंपनियों में काम किया है। कृष्णेंदु के पास ग्लोबल एक्सपीरियंस है और उनका ऑपरेशन एक्सपेंड करने और अधिग्रहण, एकीकरण और विनिवेश के माध्यम से वैल्यू क्रिएट करने का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके पास देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के साथ वैल्यूएबल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जिसकी कोर वैल्यू एर्श्र्ड के साथ रेजोनेट होती हैं।

इस माइलस्टोन पर कमेंट करते हुए, एर्श्र्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर बहिरजी ए. घोरपड़े ने कहाः ''यह हमारे मैनेजमेंट बैंडविड्थ को बढ़ाने और हमारे नेतृत्व को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक पहल है क्योंकि हम इंडस्ट्री में अपनी स्थिति को मजबूत करने की अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे हम एक सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी स्ट्रैटजिक प्रायोरिटीज के एग्जीक्यूशन को ड्राइव करने के लिए आवश्यक मैनेजमेंट बैंडविड्थ का निर्माण महत्वपूर्ण है। हम एर्श्र्ड परिवार में कृष्णेंदु और मंजूनाथ का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं।

इरेडा ने उत्तराखण्ड में स्पोर्ट साइंस सेंटर के विकास के लिए रु 1.05 करोड़ का आवंटन किया

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2024

नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के तहत नवरत्न पीएसयू इंडियन रीन्युएबल एनर्जी डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) और टीएचडीसीआईएल द्वारा स्पॉन्सर्ड गैर-लाभ पंजीकृत संस्था सेवा-टीएचडीसी के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत इरेडा द्वारा रु 1.05 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

उत्तराखण्ड के टिहरी स्थित कोटेश्वर में एक स्पोर्ट साइंस सेंटर हॉल (लगभग 298 वर्गमीटर) के विकास के लिए इस सीएसआर परियोजना को मंज़ूरी दी गई है, यह सेंटर कायकिंग और कैनोइंग में भारतीय एथलीट्स को प्रशिक्षण देगा।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मिस डयूरे शाहवार, एडिशनल जनरल मैनेजर (एचआर), इरेडा और श्री अमरदीप, जनरल मैनेजर (एस एण्ड ई), टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए। इस अवसर पर श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी (इरेडा), डॉ बिजय कुमार मोहंती, डायरेक्टर (फाइनैंस एण्ड प्रोजेक्ट्स), इरेडा, श्री शैलिंदर सिंह, डायरेक्टर (पर्सोनल), टीएचडीसीआईएल तथा इरेडा के अन्य वरिष्ठ प्रबन्धन अधिकारी मौजूद रहे।

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोन: 079-22921482 Mob.9375504122 , 9327086467 R.N.I. 63177/ 95